● वर्ष-4
● अंक-114
रायपुर, रविवार 22 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» शनिदेव को चढ़ाते हैं शमी के पत्ते

## कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैंड एंट्री

**नईदिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत राज्य के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा के लिए कुवैत पहुंचे। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा, 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा, सीरिया में बशर अल-असद के शासन के पतन के दो सप्ताह बाद और गाजा में इज़राइल और हमास के बीच संभावित युद्धविराम समझौते के संकेतों के बीच हो रही है। कुवैत की यात्रा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधान मंत्री 1981 में इंदिरा गांधी थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत किया गया। स्वागत में जुटे भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत शहर में 101 वर्षीय पूर्व इ्रुस्नस् अधिकारी मंगल सैन हांडा से मुलाकात की।

यात्रा के दौरान मोदी कुवैत के नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। कुवैत रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि शीर्ष कुवैती नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत भारत और कुवैत के बीच भविष्य की साझेदारी के लिए एक रोडमैप तैयार करने का अवसर होगी। उन्होंने कहा कि हम कुवैत के साथ पीढ़ियों से जारी ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। हम न केवल मजबूत व्यापार और ऊर्जा भागीदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता व समृद्धि से भी हमारे साझा हित जुड़े हैं। मोदी ने कहा कि वह कुवैत के अमीर, युवराज और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक को लेकर काफी उत्सुक हैं।

मोदी ऐसे समय में कुवैत की यात्रा कर रहे हैं जब दो सप्ताह पहले सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन का पतन हो गया और गाजा में इजराइल के हमले जारी हैं। मोदी ने रवाना होने से पहले दिए गए एक बयान में कहा कि कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत भारत और कुवैत के बीच भविष्य की साझेदारी का खाका तैयार करने का अवसर देगी। उन्होंने कहा कि हम कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं, जो पीढ़ियों से कायम हैं। हम न केवल व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्रों में मजबूत साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भी हमारा साझा हित है।

### यहां आने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन किसी पीएम को यहां आने में 4 दशक लग गए

पीएम मोदी ने शेख साद अल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हला मोदी कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। अपनी यात्रा के साथ, पीएम मोदी पिछले 43 वर्षों में खाड़ी देश कुवैत का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। 43 साल बाद भारत का कोई पीएम भारत दौरे पर आ रहा है। भारत और कुवैत के बीच यात्रा करने में केवल चार घंटे लगते हैं। हालाँकि, कुवैत का दौरा करने में पीएम को चार दशक लग गए। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। इसलिए मैं आज यहां सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आया हूं, आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूं।

गौरतलब है कि 9 लाख भारतीय कुवैत के कार्यबल का हिस्सा हैं, जो देश के कुल कार्यबल का 30 फीसदी है। कुल मिलाकर, खाड़ी देश की कुल आबादी में भारतीय 21 प्रतिशत (1 मिलियन) हैं। भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शामिल कुवैत का वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो देश की 3 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है।

पहली बार, कुवैत को भारतीय निर्यात 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। परंपरागत रूप से, भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जिनके संबंध तेल-पूर्व कुवैत से जुड़े हैं, जब भारत के साथ समुद्री व्यापार इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। 1961 तक, भारतीय रुपया कुवैत में वैध मुद्रा बना रहा, जो दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है।

# बीमा पर कर कटौती फिलहाल नहीं

### जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक, जीन थेरेपी में छूट

**नई दिल्ली।** जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, फोर्टिफाइड चावल की गुठली की दर में 5त्न की कमी...जीन थेरेपी जो जीवन रक्षक बीमारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, को छूट दी गई है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआर-एसएएम) प्रणाली रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सिस्टम, सब-सिस्टम, उपकरण, टूल, सॉफ्टवेयर को दी जाने वाली जीएसटी छूट को बढ़ाने का फैसला किया है। छूट को और आगे बढ़ाया गया है...व्यापारी निर्यातकों को आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर की दर को घटाकर 0.1त्न कर दिया गया है, जो ऐसी आपूर्ति पर जीएसटी दर के बराबर है।

#### एसीसी ब्लॉकों पर 12 प्रतिशत जीएसटी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 50 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉकों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। काली मिर्च चाहे ताजी हरी काली मिर्च हो या सूखी काली मिर्च और किशमिश जब किसी किसान की तरफ से आपूर्ति की जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ऋण शर्तों का पालन न करने पर बैंकों और एनबीएफसी की तरफ से वसूले गए दंडात्मक शुल्क या लेवी पर कोई जीएसटी देय नहीं है।

निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, %एजेंडे में यह अनुरोध रखा गया था कि क्या एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए... इस पर सहमति नहीं बन पाई है क्योंकि राज्य इससे सहमत नहीं हैं और यह अभी भी वहीं है जहां यह आज है... स्वास्थ्य बीमा से संबंधित निर्णयों के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। आईआरडीएआई से इनपुट की प्रतीक्षा है।%

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि, बीमा प्रीमियम पर टैक्स घटाने का फैसला भी टाल दिया गया है क्योंकि इस पर कई जानकारियां, जैसे आईआरडीएआई की टिप्पणियां, अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। वहीं बैंकों या वित्तीय संस्थानों की तरफ से उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंड शुल्क पर कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने %प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड आइटम्स% की परिभाषा में बदलाव की सिफारिश की है। जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, जिसमें एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य शुल्कों को शामिल किया गया था, तो पांच वस्तुओं-कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी कानून में शामिल किया गया था, लेकिन यह निर्णय लिया गया था कि बाद में इन पर जीएसटी के तहत कर लगाया जाएगा।

इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने आंध्र प्रदेश की 1त्न आपदा उपकर लगाने की मांग पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला किया है। यह उपकर कुछ लग्जरी सामानों पर लगाया जाएगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि इस पर सहमति बनी है कि एक त्नशरू बनाया जाए। %यह उपकर केवल लग्जरी सामानों पर और राज्य विशेष के लिए लागू होगा%। सितंबर-अक्तूबर में आंध्र प्रदेश बाढ़ से प्रभावित हुआ था।

## पूर्वोत्तर को अलग करने का आतंकी साजिश

**कोलकाता।** आतंकवादी संगठन अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश के आठ सदस्य पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले चिकन नेक को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन आठ सदस्यों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि वे कई हमलों को अंजाम देकर कॉरिडोर में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संगठन के दो सदस्यों के पास से पेन-ड्राइव और दस्तावेज बरामद किए। एडीजी सुप्रतिम सरकार ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, ये दोनों बंगाल, केरल और असम पुलिस द्वारा पकड़े गए आठ लोगों के समूह का हिस्सा थे। पूछताछ में मालूम चला कि ये सभी चिकेन नेक को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। चिकेन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है।

प्रमुख समाचार

### नक्सलियों के 40 संगठनों का खुलासा किया जाये: योगेंद्र

**लातूर ।** सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से कहा कि वे नक्सलियों के उन 40 संगठनों के नामों का खुलासा करें, जिन्होंने 'भारत जोड़ो यात्रा' में कथित तौर पर हिस्सा लिया था। उनकी मांग ऐसे समय में आई है जब दो दिन पहले फडणवीस ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि 'भारत जोड़ो यात्रा' में शामिल हुए 180 संगठनों में से 40 को महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकारों द्वारा नक्सलियों का मुखौटा संगठन घोषित किया गया था। 'भारत जोड़ो अभियान' के राष्ट्रीय संयोजक ने महाराष्ट्र के लातूर शहर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूछा, ''महात्मा गांधी के अनुयायी होने के नाते हमें नक्सलवादी कैसे कहा जा सकता है?'' एक सवाल के जवाब में यादव ने फडणवीस को इन संगठनों के नामों का खुलासा करने और यह स्पष्ट करने की चुनौती दी कि नेपाल में कथित बैठक किस बैनर तले आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि 15 नवंबर को काठमांडू में एक बैठक हुई थी।

### क्रिसमस मार्केट हमले में पांच लोगों की मौत, 300 घायल

**नई दिल्ली।** जर्मनी में एक सऊदी डॉक्टर की तरफ से क्रिसमस मार्केट में गाड़ी से रौंदने के हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। शुक्रवार की शाम को हुए इस हमले के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जर्मनी के राज्यपाल रेनर हेजलॉफ ने बताया कि मृतकों की संख्या दो से बढ़कर पांच हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि इनमें से लगभग 40 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी स्थिति चिंताजनक है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चर्च के बाहर मोमबत्तियां जलाकर और फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कई लोग वहां रोते हुए देखे गए। 2016 में एक क्रिसमस मार्केट पर हुए हमले के गवाह बने बर्लिन के एक चर्च कोयर ने अमेजिंग ग्रेस भजन गाकर अपनी प्रार्थना की।

### पूर्वांचलियों को उजाड़ने की साजिश कर रही भाजपा-आप

**नई दिल्ली।** दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचलियों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा आमने-सामने हैं। आप का आरोप है कि भाजपा पूर्वांचलियों को दिल्ली से उजाड़ने की साजिश कर रही है। भाजपा संसद में पूर्वांचल समाज के लोगों को रोहिंग्या कहकर अपमानित करने के बाद अब उनके बच्चों को प्रताड़ित करना और उनके घरों पर बुलडोजर चलाना चाहती है। पार्टी नेताओं ने कहा कि पूर्वांचल समाज को बर्बाद करने के लिए भाजपा ने दिल्ली नगर निगम (आप) में आदेश पास कराया है कि निगम के स्कूलों में पढ़ रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की जाए। आप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भाजपा अपनी साजिशों को बंद नहीं करेगी तो वह पूर्वांचल समाज के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ेगी। आप सांसद संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर एक बयान में कहा कि भाजपा यूपी, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति अपने घृणित मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है। पूर्वांचलियों को दिल्ली में बर्बाद करने की एक नई योजना लेकर आई है। उन्होंने दावा किया कि घर उजाड़ने के लिए एमसीडी से एक आदेश पारित कराया है। इसमें शिक्षा विभाग को नगर निगम स्कूलों में दाखिला देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने

### अनुमति के बिना फिर सिनेमा हॉल में पहुंचे अल्लू अर्जुन

**हैदराबाद।** तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन चार दिसंबर को उस थिएटर में पहुंचे जहां पुष्पा-2 दिखाई गई। भगदड़ के दौरान महिला की मौत के बाद भी अभिनेता सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकले। सीएम रेड्डी ने बताया कि पुलिस को उन्हें जबरन बाहर निकालना पड़ा था। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक वीडियो का हवाला देते हुए भीड़ में रोड शो करने और इस दौरान लोगों से हाथ मिलाने के लिए अल्लू अर्जुन को दोषी ठहराया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि थिएटर प्रबंधन ने दो दिसंबर को पुलिस को एक चिट्ठी देकर अल्लू अर्जून समेत अन्य लोगों के दौरे के लिए सुरक्षा की मांग की थी। थिएटर के अंदर जाने और बाहर निकलने से पहले अभिनेता अपनी कार के सनरूफ में खड़े थे। मुख्यमंत्री ने अल्लू अर्जून की गिरफ्तारी के बाद उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे फिल्मी हस्तियों की आलोचना की।

### मोहाली में पांच मंजिला इमारत गिरी

**मोहाली।** मोहाली में शनिवार शाम बड़ा हादसा हुआ है। मोहाली के सोहाना में एक पांच मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत के गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। राहत व बचाव का काम चल रहा है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने एक महिला का शव मलबे के नीचे से निकाला है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इमारत के साथ दूसरी इमारत की बेसमेंट का काम चल रहा था। बेसमेंट के लिए खुदाई की गई है। खुदाई किए जाने की वजह से इमारत की नींव हिल गई, जिससे बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। इमारत में जिम खोले गए थे। बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे 10 से 15 लोगों के दबे होने की सूचना है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। वह स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। मौके पर लोगों की खासी भीड़ लग गई है।

# आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट, घरेलू प्रवासियों की संख्या 12 फीसदी घटी

**नई दिल्ली।** भारत में 2011 से 2023 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या करीब 12 फीसदी घटकर 40.20 करोड़ पहुंच गई है, जो देश में बढ़ते आर्थिक अवसरों का संकेत देती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

ईएसी-पीएम की ओर से जारी आधार पत्र के मुताबिक, %2023 में देश में कुल 40,20,90,396 प्रवासी थे, जो 2011 की जनगणना के आंकड़ों से 11.78 फीसदी कम हैं। 2011 में यह संख्या 45,57,87,621 थी।% रिपोर्ट में कहा गया है, %कुल घरेलू प्रवासन में धीरे-धीरे कमी देखी जा रही है। हमारा अनुमान है कि 2023 तक प्रवास करने वालों की संख्या 40.20 करोड़ के आसपास रही है, जो 2011 में दर्ज संख्या से 11.78 फीसदी कम है।

रिपोर्ट के मुताबिक, घरेल प्रवास करने वालों की संख्या में गिरावट का कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और संपर्क (कनेक्टिविटी) में सुधार और आर्थिक अवसरों का विस्तार है। इन सुधारों के कारण लोग अपने घरों से दूर जाने के बजाय अपने मूल स्थानों या आसपास रहने में सक्षम हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह गिरावट आर्थिक विकास का संकेत है।

#### प्रवासन दर में कमी

इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना में प्रवासन दर 37.64 फीसदी थी। जबकि 2023 में यह घटकर 28.88 फीसदी हो गई। यह दिखाता है कि प्रवास करने की गति धीमी हो गई है, जो देश की आर्थिक स्थिति और विकास में सुधार का संकेत है।

यह रिपोर्ट तीन उच्च-आवृत्ति (हाई-फ्रीक्वेंसी) डाटा सेट का उपयोग करके तैयार की गई। पहला, भारतीय रेल अनारक्षित टिकट प्रणाली से यात्री संख्या के आंकड़े। दूसरा,

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) से मोबाइल फोन यूजर्स के रोमिंग आंकड़े और तीसरा, जिला स्तर पर बैंकिंग के आंकड़े। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके यह समझने की कोशिश की गई कि प्रवासन का असर कहां कितना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलूरू, कोलकाता जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के आने की आंकड़े अधिक हैं। यह गुरुत्वाकर्षण मॉडल (ग्रेविटी) मॉडल के अनुसार सही है, जिसमें यह माना जाता है कि प्रवास अधिकतर कम दूरी वाले होते हैं और दूरी के बढ़ने से प्रवास की संभावना घटती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जो पांच राज्य सबसे अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, उनमें बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान ने इस सूची में प्रवेश किया है, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार अब एक स्थान नीचे आ गए हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रवासियों की प्रतिशत कम हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि मुंबई, बंगलूरू, हावड़ा, मध्य दिल्ली और हैदराबाद जैसे जिले सबसे अधिक प्रवासी आकर्षित कर रहे हैं। जबकि वलसाड, चित्रदु, पश्चिम बर्धवान, आगरा, गुंटूर, विलुपुरम और साहसा जैसे जिले सबसे अधिक प्रवासियों के स्त्रोत के रूप में उभरे हैं।

### संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट: रहने लायक नहीं रहे शहर

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों व शहरों में निवास करने लगेगी। वर्ष 2001 तक भारत की आबादी का 27.81 फीसदी हिस्सा शहरों में रहता था। वर्ष 2011 तक यह 31.16 फीसदी और वर्ष 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 33.6 फीसदी हो गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 53 ऐसे शहर हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। विकास के तेज रथ पर सवार भारत के बड़े-बड़े शहर कभी प्रदूषण के गैस चैंबर बन जाते हैं, तो कभी बाढ़ में डूब जाते हैं। मिसाल के तौर पर वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में गिरावट की चिंताजनक दर यातायात की भीड़, व्यापक निर्माण से धूल और औद्योगिक प्रदूषण के कारण होती है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। भीषण गर्मियों के दौरान कूलिंग के लिए बिजली की बढ़ी मांग, भूजल के गिरते जल स्तर और पानी की कमी से इन शहरों की आबादी विकास की चमक-दमक के बावजूद त्राहि-त्राहि करने लगती है। चाहे राजधानी दिल्ली हो या फिर भारत की मिलेनियम सिटी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा गुरुग्राम या फिर भारत की व्यापार नगरी मुंबई। दरअसल, भारत के अधिकांश शहर दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जनसंख्या, ट्रैफिक जाम, पीने योग्य पानी की कमी और लगातार बढ़ते जहरीले लैंडफिल के कचरे, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय गिरावट और वायु प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और यह रहने लायक नहीं बचे हैं। उत्तर भारत के सभी नगरों समेत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में लोग वायु प्रदूषण से बेहाल,हालात का सामना करने पर मजबूर हैं।

# आरक्षण ने बदला अंबिकापुर निगम का समीकरण, कई दिग्गज नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

**सरगुजा।** छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति साफ हो चुकी है। ये तस्वीर भी अब साफ होती जा रही है कि किन वार्डों से कौन मैदान में उतरेगा। क्योंकि आरक्षण के बाद कई सीनियर नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। वहीं कई दिग्गज अब आरक्षण के हिसाब से तैयारियों में जुटे हैं।हालांकि बड़े नेताओं को संगठन चाहे तो अन्य वार्डों से भी मैदान में उतार सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी जीत की गुंजाइश कम हो जाती है। क्योंकि लोग जिस वार्ड से चुनाव लड़ते हैं, वो 15-20 वर्षो तक वहां की जनता के साथ जुड़कर सेवा करते रहते हैं। आइये जानते हैं अंबिकापुर नगर निगम में आरक्षण के बाद किस वार्ड की क्या स्थिति बनी है।

गुरुवार को नगरीय निकाय के चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण हुए। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित वार्ड आरक्षण के दौरान कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों ने पर्ची निकालकर वार्डों का आरक्षण कराया। इस दौरान एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग के आधार पर लॉटरी निकाली गई। शासन के निर्धारित आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति, महिला एवं पुरुष वर्ग से 2 सीट आरक्षित किए गए। इसके बाद अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए 8, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4, अनारक्षित महिला के लिए 8 और सामान्य वर्ग के लिए 16 वार्डों का आरक्षण किया गया।

**16 वार्ड हुए अनारक्षित :** वार्ड आरक्षण में शहर के भगवानपुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महाराणा प्रताप वार्ड, वीर संवारकर वार्ड, देवीगंज वार्ड, भगवान महावीर वार्ड, शहीद वीर नारायण वार्ड, सत्तीपारा वार्ड, गुरुनानक वार्ड, गौरीवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, ब्रम्ह वार्ड, गुरुद्वारा वार्ड, अग्रसेन वार्ड, डॉ। जाकिर हुसैन वार्ड नवागढ़ वार्ड को अनारक्षित मुक्त किया गया है।

**8 वार्ड आरक्षित महिला :** आरक्षण के दौरान मंगल पांडेय वार्ड, स्वामी विवेकानंद वार्ड, इंदिरा गांधी वार्ड, रैदास वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड, पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड, स्वामी विवेकानन्द वार्ड, डॉ। राजेंद्र प्रसाद वार्ड, कबीर वार्ड को अनारक्षित महिला घोषित किया गया है।

**अनुसूचित जनजाति महिला एवं मुक्त वार्ड :** नगरीय निकाय चुनाव में शहर के 3 वार्डों संत मदर टेरेसा वार्ड, बाल गंगाधर तिलक, गंगापुर वार्ड को अनुसूचित जनजाति महिला वार्ड घोषित किया गया। जबकि शहर के 7 वार्ड गोधनपुर, फुन्दूरडिहारी सेंट्रल, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, पटपरिया वार्ड, नमनाकला वार्ड, संत गहिरा गुरु वार्ड, बिशुनपुर वार्ड को अनुसूचित जनजाति मुक्त वार्ड घोषित किया गया है। इसी तरह शहर के डॉ। भीमराव अम्बेडकर वार्ड को अनुसूचित जाति मुक्त एवं रामानुज वार्ड को अनुसूचित जाति महिला वार्ड घोषित किया गया।

**ओबीसी मुक्त एवं महिला वार्ड :** आरक्षण के दौरान शहर के 8 वार्डों गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड, माता राजमोहिनीदेवी वार्ड, गुरुघासी दास वार्ड, शहीद भगत सिंह वार्ड, लोक नायक जय प्रकाश वार्ड, रफी अहमद किदवई वार्ड, शहीद अब्दुल हमीद वार्ड को अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त वार्ड घोषित किया गया। जबकि शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड, नेताजी सुभाषनगर बोस वार्ड, शीतला वार्ड, महामाया वार्ड को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया।

**बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद होंगे प्रभावित :** आरक्षण में शहर के कई बड़े नेताओं के वार्ड प्रभावित हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस के कई पार्षद इस आरक्षण के बाद अपने वार्डों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं परिसीमन के बाद बदली परिस्थितियों ने भी कई पार्षदों के वार्डों को प्रभावित किया है। जिसका असर आने वाले निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा।वार्ड आरक्षण में एसटी, एससी एवं महिला सीट के कारण शहर के ऐसे पार्षद प्रभावित हुए है जो पिछले दो या तीन बार से लगातार चुनाव लड़ रहे थे।

**बीजेपी पार्षदों को ज्यादा नुकसान :** आरक्षण में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी पार्षदों को हुआ है। आरक्षण में जिन पार्षदों के वार्ड प्रभावित हुए है उनमें वार्ड क्रमांक 32 शीतला वार्ड शामिल है। शीतला वार्ड पूर्व में सामान्य वार्ड था। इस वार्ड से बीजेपी मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शुक्ला पार्षद चुनकर आए थे। लेकिन आरक्षण में अब यह वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हो गया है। मधुसूदन लगातार तीन बार इस वार्ड से चुनाव जीत चुके हैं।

इसी तरह वार्ड क्रमांक 28 शहीद भगत सिंह वार्ड सामान्य से अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए आरक्षित हो गया है। इस वार्ड से पहले विकास वर्मा दो बार चुनाव जीतकर आ चुके हैं। लेकिन अब आरक्षण में वार्ड की स्थिति बदल गई है। ओबीसी मुक्त वार्ड होने से वे भी इस वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

वार्ड क्रमांक 12 माता राजमोहिनी देवी वार्ड भी पिछली बार महिला था। लेकिन इस आरक्षण में वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त को चला गया है। ऐसे में इस वार्ड से लम्बे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे रविन्द्र गुप्त भारती भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस वार्ड से रविन्द्र गुप्त की पत्नी पार्षद थी। बीजेपी पार्षद अजय सिंह बबलू का वार्ड क्रमांक 22 नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड भी अब अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हो गया है। ऐसे में इस वार्ड से भी अब ओबीसी महिला चुनाव लड़ेंगी।

**कांग्रेस के दो पार्षद भी प्रभावित:** वार्ड आरक्षण में कांग्रेस के सिर्फ दो वार्ड ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वार्ड आरक्षण में वार्ड क्रमांक 14 नमनाकला वार्ड अनुसूचित जनजाति महिला मुक्त वार्ड हो गया है। इस वार्ड से कांग्रेस से प्रमोद चौधरी चुनाव लड़कर निगम में पहुंचे थे। इसी तरह वार्ड क्रमांक 21 महात्मा गांधी वार्ड भी अब समान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया है। इस वार्ड से पहले कांग्रेस के पार्षद दीपक मिश्रा चुनाव लड़कर निगम में पहुंचे थे। इस तरह वार्ड आरक्षण में कांग्रेस के सिर्फ दो बड़े चेहरे के वार्ड प्रभावित हुए है।

# अनुसुचित जाति व जनजाति के युवाओं को ऋण देने में ढिलाई

## कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को लगाई फटकार

**बलौदाबाजार।** अनुसूचित जनजाति के युवाओं को ऋण देने में कोताही बरतने और शासकीय योजनाओं पर त्वरित क्रियान्वित नहीं करने पर कलेक्टर दीपक सोनी ने बैंक अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कही।

जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में बैंकों की कार्यप्रणाली से कलेक्टर नाखुश नजर आए। कलेक्टर दीपक सोनी ने दो टूक कहा है कि सरकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को दिए जा रहे अनुदान राशि का समायोजन उनके द्वारा निजी तौर पर लिए गए बैंक ऋण के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कुछ बैंकों द्वारा ऐसी हरकतों की शिकायत मिलने पर इस आशय के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देने में रुचि नहीं दिखाने पर बैंक अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता और एलडीएम बिनाय राय चौहान विशेष रूप से उपस्थित थे।

कलेक्टर सोनी ने परामर्शदात्री समिति की तिमाही समीक्षा बैठक में बैंकों के काम-काज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बैंक लोन का प्रवाह ग्रामीणों और किसानों की ओर प्राथमिकता से ज्यादा होने चाहिए। रिज़र्व बैंक के इस सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिये।

कलेक्टर ने जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग, खादी ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय शहरीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविक मिशन, जिला अंतयाव्यसायी सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं में अधिक ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और जीवन सुरक्षा योजना क्षतिपूर्ति की भी जानकारी ली।

कलेक्टर ने पंचायत सचिव और सांख्यिकी विभाग से मृत्यु के आंकड़ों से मिलान कर शत-प्रतिशत हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग की योजनाओं में भी अपेक्षित प्रगति नहीं मिली है। कलेक्टर ने योजनाओं में अत्यंत धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी दिखाई। बैंकों में प्रस्तुत 123 प्रकरणों में केवल 25 प्रकरण ही स्वीकृत किये गए हैं। उन्होंने 10 जनवरी तक सभी पुराने प्रकरणों का निराकरण करने के लिए बैंकों को निर्देशित किया। इसके साथ ही अंत्यावसायी समिति के अधिकारियों को बैंकों में लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण भेजने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरणों में जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए। यदि कोई केस स्वीकृत करने योग्य नहीं है,तो उचित कारण बताते हुए निरस्त किया जाये। एलडीएम चौहान ने कलेक्टर के निर्देश और समिति में लिए गए निर्णयों के अनुरूप भविष्य में प्रगति लाने का बैंकों की ओर से भरोसा दिलाया और अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया।

# ट्रांसपोर्टर के पास 10 से कम गाड़ियां तो नहीं कटेगा टीडीएस

## आयकर विभाग का अवेयरनेस सेमिनार

**कोरबा।** टीडीएस की कटौती से संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए आयकर विभाग की टीडीएस शाखा की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ट्रांसपोर्टर्स शामिल हुए। ट्रांसपोर्टर्स को आयकर विभाग के अधिकारियों ने टीडीएस के प्रावधानों के बारे में बताया और उनके सवालों का जवाब दिया। इस दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने टीडीएस को लेकर कई सवाल भी आयकर विभाग के अधिकारियों से पूछे। अधिकारियों ने भी सहजता से इन सवालों का जवाब दिए।

कार्यशाला में आयकर विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसपोर्टर्स को बताया कि जिनके पास 10 से कम गाड़ियां हैं। उनका टीडीएस नहीं काटा जा सकता। ट्रांसपोटरों ने आयकर विभाग के अधिकारियों को बताया कि कई कंपनियां है, जो उनसे टीडीएस तो काट रहीं है। लेकिन इसे समय पर जमा नहीं कर रही हैं। तब आयकर विभाग के कर्मचारियों ने इन कंपनियों के विरूद्ध आयकर के टीडीएस शाखा में शिकायत करने को कहा ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस कार्यशाला में आयकर विभाग के टीडीएस शाखा रायपुर के अपर आयुक्त अनुभा गोयल के अलावा सहायक आयकर आयुक्त बिलासपुर लेजू जेकब और आयकर अधिकारी अंजनी कुमार उपस्थित थे।

ट्रक मालिक संघ संरक्षक अरुण कुमार शर्मा ने कहा टीडीएस की तरफ से कार्यक्रम था। हमें बताया गया कि जिनके पास 10 से कम गाड़ियां है, उनका टीडीएस नहीं कटेगा। लोगों की शिकायत है कि हर गाड़ी का टीडीएस कट रहा है लेकिन इसे जमा नहीं किया जा रहा है। इनकम टेक्स ने बताया कि गाड़ी वाले का टीडीएस यदि गाड़ी वाले को दिया जाएगा तो इससे उसका इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ने से प्रॉफिट के आधार पर बैंक में फाइनेंस में आसानी होगी।

कार्यक्रम के दौरान कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि कई कंपनियां उनसे टीडीएस की कटौती कर रही हैं। लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। टीडीएस चेक करने पर कटौती भी नहीं दिखाता है। तब आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसी कंपनियों के संबंध में ट्रांसपोटरों को आयकर विभाग के टीडीएस शाखा में एक शिकायत करनी होगी। इसके बाद विभाग संबंधित संस्थान या बैंक को नोटिस देकर कटौती के बारे में जानकारी मांगेगा।

अगर कटौती पाई जाती है तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला के दौरान ट्रांसपोटरों को बताया गया कि उनका टीडीएस कटता है, तो इससे उनके फर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है और बैंक से लोन लेने में आसानी होती है। ट्रांसपोटरों को टीडीएस कटौती के फायदे से अवगत कराया गया। कार्यशाला में कोरबा के 30 से 40 ट्रांसपोटर शामिल हुए। इसमें संघ के संरक्षक अरूण शर्मा भी शामिल हुए। चेंबर भवन में आयोजित इस कार्यशाला में कई ट्रांसपोटरों ने अपने सवाल किए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

## जंगल में नीलगाय का शिकार तीन आरोपी गिरफ्तार

**कबीरधाम।** कबीरधाम जिले में वन्यप्राणी के शिकार का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वन परिक्षेत्र सहसपुर लोहारा के जंगल में एक नीलगाय का शिकार किया है। विभाग ने तीन आरोपी को गिरफ्तार किया है, एक अन्य आरोपी फरार है। सहसपुर लोहारा के उप वनमंडलाधिकारी अनिल साहू ने बताया कि ग्राम मोहनपुर के निवासी प्रताप पिता मेहतर नेताम के निवास पर सर्च वारंट जारी कर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान प्रताप के घर के अंदर से जंगली जानवर का मांस, औजार समेत अन्य सामान बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान प्रताप ने बताया कि उसके साथ मुंशी पिता जनार्दन यादव, अनिल पिता गोकर्ण नेताम, विश्वनाथ पिता महावीर ने जंगली जानवर की शिकार को अंजाम देने मोहनपुर परिसर से लगे जंगल पीएफ 258 में करंट तार बिछाकर नीलगाय का शिकार किया। इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर आपस में बांट लिया। शिकार में प्रयुक्त टंगिया को अनिल की निशानदेही पर बरामद किया है। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

## ग्राम पंचायत पतोरा के सरपंच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

**उतई।** जनपद पंचायत पाटन के ग्राम पंचायत पतोरा के सरपंच अंजिता साहू के बर्खास्तगी और 6 साल के लिए चुनाव नहीं लडने पर प्रतिबंध के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि यह राजनीति से प्रेरित था। उल्लेखनीय हैं कि अनुविभागीय दंडाधिकारी पाटन लवकेश ध्रुव ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत जपं पाटन के ग्राम पंचायत पतोरा के सरपंच अंजिता साहू बर्खास्त कर दिया था।साहू के ऊपर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के आय व्यय में गड़बड़ी एवं गांव के जर्जर स्कूल के डिस्मेंटल के बाद सामग्रियों का स्टॉक पंजी नहीं बनाए जाने और विधिवत नीलाम नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए बर्खास्त करने का फैसला सुना दिया गया, साथ ही उसे 6 साल के लिए चुनाव लडने के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया। एसडीएम द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सरपंच अंजिता गोपेश साहू ने उच्च न्यायालय बिलासपुर के याचिका दायर की थी जिस पर न्यायमूर्ति ने पतोरा सरपंच अंजिता साहू के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दिया।

## आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन धमतरी जिले ने मारी बाजी

**धमतरी।** छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में घर घर पहुंचकर 70 एवं 70+ आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदन कार्ड पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन कराने के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक अनिवार्य है। धमतरी जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्राम पंचायतों, ग्राम और शहरों में शिविर लगा रही है। शिविर स्थल में नहीं पहुंच पाने वाले वृद्धजनों का घर घर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यही वजह है कि धमतरी जिला आयुष्मान वय वन्दना कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर है। धमतरी जिले में अब तक 5 हजार 700 से ज्यादा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक मुफ्त उपचार लाभ की सुविधा मिलती है। धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने जिले के सभी वरिष्ठ नागरिकों को जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या च्वाइस सेंटर, आधार सेवा केन्द्र में उपस्थित होकर आयुष्मान वय वन्दना कार्ड पंजीयन कराकर योजना का लाभ लेने की अपील की है।

## टैंकर और बस के बीच जोरदार टक्कर, दर्जनों यात्री हुए घायल

**जांजगीर चांपा।** जांजगीर चांपा जिले के ग्राम राछा चौक के पास तेज रफ्तार टैंकर वाहन और बस में आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक दर्जन यात्री घायल हुए हैं। टैंकर वाहन भी पलट गया। उसके चालक को भी चोट आई है। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी अनुसार, नवागढ़ बस स्टैंड से शुक्ला बस जोकि जांजगीर आ रही थी। वहीं, जांजगीर की तरफ से टैंकर नवागढ़ की ओर जा रहा था। तभी राछा चौक के पास टैंकर के चालक ने लापरवाही पूर्वक बस को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार दर्जन भर यात्री घायल हो गए। वहीं, टैंकर को लेकर चालक भागने की कोशिश कर रहा था। मगर रफ्तार कम नहीं होने के कारण चौक से 300 मीटर की दूरी पर जाकर पलट गया। जिससे टैंकर के चालक को भी चोट आई है। सभी का उपचार सीएचसी अस्पताल नवागढ़ में जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे घटना की जांच पड़ताल कर रही है, टैंकर को जब्त किया है।

## पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा और घाटी में फेंक दिया

**कोरबा।** कोरबा के बांगो थाना अंतर्गत पतोड़ियाडांड निवासी 28 वर्षीय विशाल आरमो और 24 वर्षीय उसकी पत्नी गनपति अपने 3 साल के लड़के और ढाई माह की बच्ची के साथ पैदल गांव से लगे अरसिया गांव के जंगल घूमने गए हुए थे। जहां घूमने के बाद शाम होने से पहले घर वापस लौट रहे थे। गनपति बाई घाटी चढ़ते समय थक गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। इस बीच विशाल आरमो को गुस्सा आ गया और अपनी पत्नी गनपति को मुक्का से मारपीट करने लगा डर में वो फिर से चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो फिर थककर बैठ गई, उसके पति विशाल को फिर गुस्सा आया और उसने डंटे और मुक्के से बेरहमी जमकर पिटाई कर दी और उसे घाटी में फेंक दिया। उसके बाद दोनों बच्चों को लेकर घर चला आया। और घर वालों को बताया कि वह घाटी में अचानक गिर गई। रात में मृतका घाटी में ही पड़ी रही। इसकी सूचना उसने बांगो थाना पुलिस को मौके पर पहुंचे। जांच की गई तो गनपति की मौत हो चुकी थी। मृतका के पिता को उसके दामाद पर शक हुआ।

# पटवारी कार्यालय के लिए आरक्षित जमीन पर बनवा दी दुकानें

■ ग्राम पंचायत और निगम प्रशासन की मनमानी

**बिलासपुर।** बिलासपुर जोन कार्यालय 7 में पटवारी कार्यालय के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर नियम को ताक पर रखकर दुकानें बना दी गई और चहेते लोगों को बांट दिया गया। यह आरोप स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत और निगम प्रशासन पर लगाया है। इस मामले में अफसरों का कहना है कि शिकायत पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सरकंडा क्षेत्र के मोपका इलाके का है।

बता दें कि बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र के अंतर्गत मोपका इलाके में सड़क किनारे सरकारी भूमि पर पटवारी कार्यालय के लिए जमीन आरक्षित रखी गई थी, लेकिन पंचायत ने इसमें दुकान का निर्माण का प्रस्ताव पारित कर दिया और निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी बीच इस निर्माण पर कोर्ट से स्टे हुआ तो काम को बंद कर दिया गया।

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कुछ समय के बाद इस क्षेत्र को परिसीमन में शामिल कर निगम क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद निगम उक्त भूमि को अपने अधिपत्य में लेकर स्टे हटवाकर पुन: निर्माण कार्य को कराकर दुकानें बनवा दी। बगैर सूचना के अपने-अपने लोगों को सस्ते दरों में दुकानें भी दे दी। इस मामले में जोन कमिश्नर ने कहा कि पंचायत द्वारा दुकान का निर्माण कराया गया था। निगम में शामिल होने के बाद निगम ने जर्जर दुकानों का मरम्मत कराया है। पटवारी कार्यालय के लिए जगह आरक्षित होने की जानकारी नहीं है। इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

# धान खरीदी केंद्र में घुसकर भालू ने किया हमला

**कांकेर।** शहर के एक धान खरीदी केंद्र में भालू के घुस आने से हड़कंप मच गया। यहां भालू ने एक मजदूर पर हमला करके घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद भालू को खरीदी केंद्र से खदेड़ा है। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। पूरा मामला अल्नियापारा धान खरीदी केंद्र का है। जहां अचानक भालू घुस आया। जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान भालू ने एक व्यक्ति पर हमला भी कर दिया। मजदूर के चेहरे और हाथ में चोट आई है। जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने भालू को खदेड़ा और मजदूर की जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची गई है।

# भड़काऊ भाषण पर कांग्रेस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज

■ भाजपा नेताओं ने की थी पुलिस में शिकायत

**सारंगढ़-बिलाईगढ़।** प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण व अमर्यादित बयान पर कांग्रेस विधायक उत्तरी गनपत जांगड़े के साथ नपा अध्यक्ष सोनी बंजारे के पति अजय बंजारे के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। मामले में भाजपा पदाधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई थी।

एएसपी निमिषा पाण्डेय ने बताया कि कल भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लिखित आवेदन पेश किया था। इस पर प्रथम दृष्टया दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 56, 351(1)(ड), 352, 296 के तहत मामला पंजीबध किया है।

क्या था मामला

बता दें कि दो दिन पहले छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े के भड़काऊ भाषण का वीडियो सामने आया था। इसमें जांगड़े कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़-फोड़ की बात कह रही हैं। साथ ही बलौदाबाजार की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया था। इस वीडियो को बीजेपी ने शेयर कर लिखा कि कांग्रेस इस तरह से जहर घोलने का काम करती है।

दरअसल, यह वीडियो कांग्रेस के किसी प्रदर्शन और घेराव कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इसमें उत्तरी जांगड़े युवाओं को ये कह रही हैं कि कलेक्ट्रेट के भीतर जाना है, केवल बाहर से ही नहीं आना है। हम सबको एक साथ जाकर तोड़-फोड़ कर आना है। बलौदाबाजार कैसा है, ये तो आप जान ही रहे हैं।

यह प्रदर्शन उत्तरी जांगड़े के पति गनपत जांगड़े सहित छह लोगों के खिलाफ धान गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में कलेक्टोरेट का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उत्तरी जांगड़े ने यह विवादास्पद बयान दिया था।

## संक्षिप्त समाचार

### नान घोटाला मामले की सीबीआई करेगी जांच, सरकार ने जारी की अधिसूचना

**रायपुर।** ईओडब्ल्यू में पद का दुरुपयोग करने मामले में दर्ज एफआईआर की अब सीबीआई जांच करेगी। इसकी अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। इस मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद वर्मा, पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को आरोपी बनाया गया है। यह मामला छत्तीसगढ़ के नान घोटाले से जुड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में 13 हजार 301 दुकानों में राशन बांटने में गड़बड़ी की गई है। अकेले चावल में ही 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कुल घोटाला एक हजार करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि स्टॉक वैरिफिकेशन नहीं करने के बदले में एक-एक राशन दुकान वाले से 10-10 लाख रुपए लिया गया था। कांग्रेस सरकार में महाधिवक्ता रहे सतीश चंद्र वर्मा इस मामले में जांच के दायरे में हैं। उन पर और उनके साथ अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने गवाहों पर दबाव डाला और उनके बयान बदलवाए। 4 नवंबर को ईओडब्ल्यू ने नान घोटाले में एक नई एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

### 23 को यूथ कांग्रेस बढ़ते अपराध के खिलाफ सीएम हाउस का करेगें घेराव

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और

नशाखोरी को लेकर युवा कांग्रेस रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। राजीव भवन में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शेषनारायण ओझा ने कहा, नशा और अपराध को लेकर यूथ कांग्रेस 23 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। ओझा ने कहा, 24 दिसंबर को बिलासपुर में नशे के खिलाफ हॉफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा, 23 दिसंबर को सीएम हाउस घेराव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत सभी प्रमुख नेता और प्रदेशभर से हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। गांधी मैदान में सुबह 11 बजे पहले सभा होगी, फिर सीएम हाउस घेराव करने निकलेंगे।

### राजधानी में सुबह-सुबह पुलिस की सरप्राइज चेकिंग, 15 संदिग्ध हिरासत में

**रायपुर।** राजधानी पुलिस ने शनिवार सुबह-

सुबह बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए सरप्राइज चेकिंग किया। सुबह 5 बजे जिले के 3 एडिशनल एसपी, 3 सीएसपी, 4 थाना प्रभारी और 150 पुलिस बल ने एक साथ मुजगहन थाना क्षेत्र के बीएसयूपी कॉलोनी में दबिश दी, जिससे अपराधी कांप उठे। पुलिस ने वहां चाकूबाजी, नशीली दवाई की बिक्री करने वाले कई संदिग्धों और फरार आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 15 से संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दरअसल, पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि कॉलोनी में बहुत से लोग सूने मकानों के ताले तोड़कर वहां कब्जा कर रह रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं और बिना किसी पहचान पत्र के निवास कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग नशीले पदार्थों की बिक्री करते हैं और कुछ चाकूबाजी की घटनाओं में भी संलिप्त हैं। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद आज सुबह कॉलोनी में रह रहे संदिग्धों पर शिकंजा कसा है।

### डीजीपी की रेस में सबसे आगे अरुण देव गौतम का नाम

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ के नए पुलिस प्रमुख (डीजीपी) के लिए नाम लगभग फाइनल हैं केवल विभागीय तौर पर आदेश जारी होना बाकी है। यह नाम हैं अरुणदेव गौतम का। 1992 बैच के आईपीएस अफसर देव छत्तीसगढ़ कैडर से हैं

और वरिष्ठता के लिहाज से उनका डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। बता दें कि वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी, 2025 को पूरा होने वाला है। जुनेजा का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम शॉर्टलिस्ट करके केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था।

# पत्रकार के साथ दुर्व्यहार, विधानसभा में धमकी देना गैरसंवैधानिक: भाजपा

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक पत्रकार के साथ दुर्व्यहार को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। जमकर आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब इस मामले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायकों ने पत्रकार के साथ की धक्कामुक्की और बदसलूकी की। लोकतंत्र के मंदिर में कांग्रेस की गुंडागर्दी शर्मनाक है। लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर देशभर में ढोल पीटते कांग्रेसी संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी का सरेआम मखौल उड़ाकर लोकतंत्र का गला घोंट रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि शुक्रवार को विधानसभा में पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करके न केवल अपने कलंकित राजनीतिक चरित्र का परिचय दिया है, बल्कि उसने यह धारणा भी पुष्ट कर दी है कि कांग्रेस अब पूरी तरह हिंसक चेहरा अपना दिखा रही है। एक तरफ गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रहते बुजुर्ग सांसदों के साथ धक्कामुक्की करके उनका सिर फोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने कांग्रेस के नेताओं को खुला आह्वान किया है कि जैसे बलौदाबाजार में किया था, ठीक वैसे ही कलेक्ट्रेट के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करें। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में पत्रकार के सवाल पूछे जाने पर पहले पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें उंगलियां दिखाईं और फिर कांग्रेस विधायकों ने घेरकर उसके साथ धक्कामुक्की की। पत्रकार को धमकाते हुए औकात में रहने की बात कही। उससे अभद्रता की, उसका माइक और कैमरा छीन लिया। ऐसा दृश्य किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित समाज के लिए बेहद शर्मनाक है।

उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर कांग्रेस केवल हिंसा कर रही है। छत्तीसगढ़ में और विशेषकर विधानसभा परिसर में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया कि जब पत्रकार को घेरकर उसे घुटनों के बल बिठाने का प्रयास किया गया हो, किसी पत्रकार का माइक खींचा गया हो, कैमरा छीन लिया गया हो और उस पत्रकार को कहा गया हो कि तू अपनी औकात में रह। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस प्रकार का बर्ताव निंदनीय है। कांग्रेस ने जो कृत्य शुक्रवार को प्रदेश की विधानसभा में किया है। वह माफी लायक कतई नहीं है।

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कांग्रेस से पूछा है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि कांग्रेस को विधानसभा में झूठ बोलना पड़ा? पूर्व मुख्यमंत्री जिस विधानसभा का मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल नेतृत्व करते रहे उन्हें आखिर वहां महाझूठ क्यों बोलना पड़ा? जिस पत्रकार के साथ कांग्रेस के लोगो ने धक्कामुक्की की, उसे धमकाया। उसे भूपेश बघेल ने फर्जी पत्रकार बताया और कहा कि वह पत्रकार के भेस में घुस आया था यह सिक्योरिटी लेप्स का मामला है जबकि पत्रकार सुनील नामदेव के पास न सिर्फ 16 से 20 दिसंबर 2024 तक हुए विधानसभा सत्र का प्रवेश पास था बल्कि वह छत्तीसगढ़ विधानसभा पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं, जिसमें प्रदेश के कुछ चुनिंदा पत्रकार ही सदस्य हैं।

अमित ने कहा एक पूर्व मुख्यमंत्री जो पांच साल तक जिस विधानसभा का नेतृत्व करते रहे उन्हें झूठ बोलते हिचक क्यों नहीं हुई? पूर्व मुख्यमंत्री का यह कृत्य विधानसभा के प्रति लोगों के विश्वास पर आघात करने वाला कृत्य है। विधानसभा में कहे गए शब्दों को जनता पूर्णतः सत्य मानती है विधानसभा के प्रति जनता श्रद्धा भाव रखती है। ऐसे में एक पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में इस प्रकार से झूठ कहना, जनता को गुमराह करना, न सिर्फ निंदनीय है बल्कि और गैरसंवैधानिक भी है। जिस संविधान को हाथ में लेकर कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं, उसी संविधान की धज्जियां वह रोज उड़ा रहे हैं।

# आईएमए भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ देंगे: स्वास्थ्य मंत्री

**▪ डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल से और भी विषयों पर हुई सार्थक चर्चा**

**रायपुर।** विगत दिनों स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल व विभाग के अधिकारियों के साथ डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 3 घंटे की मैराथन बैठक की जिसमें कई विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में डॉ कुलदीप सोलंकी,डॉ केतन शाह व डॉ संजीव श्रीवास्तव डॉ पुर्णेन्दु सक्सेना,डॉ विमल चोपड़ा,डॉ कमलेश्वर अग्रवाल,डॉ सुरेन्द्र शुक्ला,डॉ अखिलेश दुबे व अन्य शामिल थे। बैठक में जिस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंत्री जी ने सहमति दी वह था 30 बिस्तर वाले अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट से अलग कर सरलीकरण किया जाना।

आयुष्मान भारत योजना के लिए 600 करोड़ रुपए जारी किया जाने की जानकारी दी। इस पर चिकित्सकों ने आग्रह किया कि स्वास्थ्य मंत्री को जब इस बात से अवगत कराया गया कि रायपुर आईएमए को पूर्व में भाजपा शासनकाल में सरकार ने कालीबाड़ी चौक में करीब 12 हजार वर्गफीट जमीन का आबंटन किया था। जिसमें राजधानी की गरिमा के अनुरूप आईएमए भवन का निर्माण हो ऐसी प्राथमिकता के साथ योजना प्रस्तावित हैं। भवन में सेमीनार हाल, जिम, रिक्रियेशन हाल और प्रदेश के बाहर से आने वाले सदस्यों को रुकने के लिए 10 कमरे व 24 घंटे संचालित होने वाले कैंटिन की व्यवस्था हो। चिकित्सा से संबंधी सभी प्रकार के सेमीनार,सम्मेलन या अन्य कार्यक्रम आईएमए भवन में हो जो आयोजकों को रियायती दर पर उपलब्ध हो सके। डॉ सोलंकी ने मांग रखी की कि आप लोगों ने -आईएमए को जमीन दी है और आप लोग ही भवन निर्माण में सहयोग करेंगे। इस पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने 1 करोड़ रुपए का सहयोग भवन निर्माण के लिए देने का आशवासन दिया। डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने पुनः आभार जताया। कल हुई बैठक में डॉ विमल चोपड़ा,डॉ सुरेन्द्र शुक्ला,डॉ कुलदीप सोलंकी,डॉ केतन शाह,डॉ संजीव श्रीवास्तव,डॉ शैलेश खंडेलवाल,डॉ अजय अग्रवाल,डॉ अनिल कर्णावट,डॉ आनंद जायसवाल,डॉ किशोर सिंह,डॉ पी यू सक्सेना,प्रेम चौधरी शामिल थे।

### राहुल पर एफआईआर को लेकर अमरजीत भगत का बड़ा बयान

**रायपुर।** राहुल गांधी पर हुए एफआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी देश के नेता हैं, संविधान देश की आत्मा है। राहुल गांधी पर आंच भी आएगी तो लोग जान दे देंगे।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से इस्तीफा देकर निकले नेताओं की फिर से कांग्रेस में वापसी होने जा रही है। वहीं कांग्रेस में प्रवेश लेने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इसे लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रवेश के लिए समिति बनाने का निर्णय अच्छा है। इससे किसी एक नेता की नहीं चलेगी, समिति फैसला लेगी। किसी ने भूल मान लिया तो उसे माफ कर देना चाहिए।

वहीं बृहस्पत सिंह के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से माफी मांगने को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि दोनों के बीच अंतरंग संबंध है, हमने करीब से देखा है। उन्होंने इसे लेकर कहा- क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात।

प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी सियासत तेज है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने घुसपैठियों की सूची और फोटो जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची जारी करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ दावा करती है, अब तक किसी को पकड़ नहीं पाए। विजय शर्मा युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, पर उनके लिए, यह काम आसान नहीं है।

# सीखने के लिए सदैव सतत् इच्छा होनी चाहिए: डेका

**रायपुर।** जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है और सीखने के लिए सदैव एक सतत् इच्छा होनी चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छे ईसान बनें क्योंकि अच्छे व्यक्ति ही बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। यह उद्गार राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज यह विचार आईसीएफएआई विश्वविद्यालय रायपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया।

दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले 21 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 18 विद्यार्थियों को रजत पदक सहित 362 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की अधिक संख्या है। यह देख कर उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि महिला सशक्तिकरण दिन ब दिन बहुत बेहतर हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करें तो सफलता निश्चित है। उज्जवल भविष्य के लिए इच्छा शक्ति और अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। समाज आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है उसके लिए काम करें। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की मेहनत और योग्यता से भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। निजी उच्च शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें और शिक्षा का स्तर बढाएं। शिक्षा एक ग्लोबल व्यवसाय है। केवल विशाल भवन बनाकर शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना जरूरी है। शिक्षा केन्द को एक व्यवसाय का संस्थान न बनाया जाए। राज्यपाल ने पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि हमेशा श्रेष्ठता की ओर बढ़ते रहें। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर आर. पी. कौशिक ने भी अपना संबोधन दिया। कुलपति डॉ. एस. पी. दुबे ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

# विष्णुदेव सरकार ने सुबोध को दिल्ली से क्यों बुलाया छत्तीसगढ़?

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) 1997 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर सुबोध कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सिंह पिछले पांच साल से डेपुटेशन पर दिल्ली में कार्यरत थे। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के बाद इस पद पर पदस्थ किया गया है।

सुबोध कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के ऑफिसर हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के बाद वो माना एयरपोर्ट से सीधे मंत्रालय गए। वहां उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की और अपनी ज्वॉइनिंग दे दी है। वो छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईएएस हैं। रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। हाल ही में केंद्र सरकार में स्टील मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी और वित्तीय सलाहकार के पद पर थे। राज्य सरकार के अनुरोध पर वो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस छत्तीसगढ़ लौटे हैं।

सबसे बड़ी और खास बात ये है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान उनसे अनुरोध किया था,

जिसके बाद उन्होंने सुबोध सिंह को छत्तीसगढ़ जाने का आदेश जारी करवाया। इसके बाद सुबोध कुमार सिंह छत्तीसगढ़ पहुंचे। बीते दिनों ही उन्हें पोस्टिंग भी मिल गई। उन्होंने अपना पद्भार भी ग्रहण कर लिया है। रमन सिंह सरकार में वो करीबी अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनकी छवि ईमानदार और प्रभावी ऑफिसर के रूप में होती है। रमन सिंह सरकार में उन्होंने कई बेहतर कार्य किया था। मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

साल 2018 में 15 साल की रमन सरकार के जाने के बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और सुबोध सिंह सहित कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिल्ली डेपुटेशन पर भेजे गए थे। दिल्ली में उन्हें जनवरी 2020 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया। फिर जून 2023 में उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब सुबोध सिंह को वापसी मुख्यमंत्री सचिवालय छत्तीसगढ़ में प्रमुख सचिव के रूप में हुई है।

जून 2023 में सुबोध कुमार सिंह को एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे।

आईएएस की ट्रेनिंग के बाद 2018 में उनकी पहली पोस्टिंग मंडला जिले में असिस्टेंट कलेक्टर पद पर मिली थी। इसके बाद वह कोरिया जिले के एसडीओ बनाए गए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वह बस्तर जिले के पहले जिला पंचायत सीईओ बने। इसके बाद साल 2002 में उनकी नियुक्ति रायगढ़ डीएम के रूप में हुई। वे रायपुर और बिलासपुर के भी कलेक्टर रह चुके हैं। दिल्ली में उन्हें जनवरी 2020 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया। फिर जून 2023 में उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसके अलावा वो कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में सचिवों की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में सबको विभाग मिलना कठिन हो गया है। अगले महीने दस और आईएएस ऑफिसर सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। पहले जहां सचिवों की संख्या कम थी। वहीं अब परफॉर्मेंस को महत्व दिया जा रहा है। केवल परिणाम देने वाले अधिकारियों को ही विभाग मिलेंगे। इसके अलावा कुछ सचिवों के ऊपर भी प्रमुख सचिव नियुक्त किए जा सकते हैं।


## छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग कार्यालय कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

**ई. प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना**

Main Portal: http://cgeprocurement.gov.in
WRD Portal:http://wrd.cgeprocurement.gov.in

**निविदा निरस्तीकरण सूचना**

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक 159716, 159717, 161263, 161334, 161335, 161336, 161337, 161338, 161339, 161340, 161341,161342, 161345, 161346 जिसका जी नंबर 242503209, 242503210 दिनांक 16.10.2024 एवं 242503970, 242503978 दिनांक 21.11.2024 है, को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

कार्यपालन अभियंता
टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग,
जगदलपुर, जिला - बस्तर. (छ.ग.)

जी-242504705/9


### कांग्रेस में जेसीसीजे के विलय पर साव का बड़ा बयान

# कांग्रेस में मतभेद की स्थिति, कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे नेता

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ की सियासत में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) और बागी नेताओं की कांग्रेस पार्टी में वापसी की चर्चा जोरों पर है। इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, मतभेद की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने स्पष्ट रूप से नकार दिया है। आने वाले दिनों में भी स्थिति और स्पष्ट नजर आ रही है।

भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बीजेपी संविधान के हिसाब से चलती है। सुव्यवस्थित से तरीके से सर्वानुमति बनाकर करने का काम हो रहा है। प्राथमिक सदस्यता और सक्रिय सदस्यता के लिए भी अभियान चलाए गए। एक-एक बूथ में कमेटी, बूथ के बाद मंडलों और जिलों की रचना हुई है। जिले के बाद प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होगा।

बता दें कि हाल ही में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. रेणु जोगी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर विलय का प्रस्ताव भेजा था। पत्र में लिखा कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की गठित पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की है। पार्टी की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पार्टी का कांग्रेस में विलय हो। सभी पदाधिकारी और सदस्य कांग्रेस में प्रवेश करना चाहते हैं। डॉ. रेणु जोगी ने प्रवेश कराने का अनुरोध किया है।


## कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अधीक्षक जिला चिकित्सालय बा.बाजार छ.ग.

E-mail Id s-bbazar.cg@gov.in.csbalodabazar2013@yahoo.com Telephon 07727-223532

क्रमांक/सी.एस/2024/4533 बलौदा बाजार दिनांक 20/12/2024

**जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार में पार्किंग व्यवस्था हेतु निविदा सूचना बाबत् विज्ञप्ति**

**द्वितीय आमंत्रण**

जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार के पार्किंग व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा प्रपत्र की शर्तो एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में किसी भी दिवस (शासकीय अवकाश को छोड़ कर) में प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 500.00 (अक्षरी पांच सौ रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट जीवनदीप समिति जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार के नाम से) जमा कर प्राप्त कर सकते है।

| | |
|---|---|
| निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक | - 01.01.2025 को सायं 5.00 बजे तक |
| निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक | - 02.01.2025 (गुरुवार) दोपहर 3.00 बजे तक |
| निविदा खोलने की तिथि दिनांक | - 02.01.2025 (गुरुवार) सायं 04:00 बजे से |

निविदा खोलने की तिथि एवं समय में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन किया जा सकता है जिसकी सूचना कार्यालय के सूचना पोर्टल मे चस्पा कर दी जावेगी।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार छ.ग.

जी-242504741/3



## कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, बस्तर मण्डल, जगदलपुर

**ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना**

https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-
निविदा डाऊनलोड करने की अंतिम तिथि :- 30/12/2024

| स. क्र. | नि.आ.सू.क्र./ नि.आ.सू. दिनांक | सिस्टम निविदा क्रमांक निविदा का क्रम | कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 79/2024-25 दिनांक 17/12/2024 | 162995 (प्रथम आमंत्रण) | उपसंभाग लोहण्डीगुड़ा के अंतर्गत बारसूर सेक्शन के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य। | 30.00 |
| 2 | 80/2024-25 दिनांक 17/12/2024 | 162999 (प्रथम आमंत्रण) | उपसंभाग बस्तर के अंतर्गत भानपुरी सेक्शन के आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य। | 7.00 |
| 3 | 81/2024-25 दिनांक 17/12/2024 | 163000 (प्रथम आमंत्रण) | उपसंभाग दरभा के अंतर्गत आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य। | 10.00 |
| 4 | 82/2024-25 दिनांक 17/12/2024 | 163001 (प्रथम आमंत्रण) | उपसंभाग दरभा के अंतर्गत गैर आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य। | 35.00 |
| 5 | 83/2024-25 दिनांक 17/12/2024 | 163003 (प्रथम आमंत्रण) | उपसंभाग दरभा के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत कार्य। | 10.00 |
| 6 | 84/2024-25 दिनांक 17/12/2024 | 163004 (प्रथम आमंत्रण) | उपसंभाग दरभा के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत कार्य। | 20.00 |
| 7 | 85/2024-25 दिनांक 17/12/2024 | 163005 (प्रथम आमंत्रण) | उपसंभाग बस्तर के अंतर्गत भानपुरी सेक्शन के गैर-आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य। | 7.00 |
| 8 | 86/2024-25 दिनांक 17/12/2024 | 163006 (प्रथम आमंत्रण) | उपसंभाग दरभा के अंतर्गत के मार्गो एवं पुल-पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य। | 30.00 |
| 9 | 87/2024-25 दिनांक 17/12/2024 | 163007 (प्रथम आमंत्रण) | उपसंभाग दरभा के अंतर्गत के मार्गो एवं पुल-पुलियों का साधारण मरम्मत कार्य। | 10.00 |
| 10 | 88/2024-25 दिनांक 17/12/2024 | 163008 (प्रथम आमंत्रण) | उपसंभाग दन्तेवाड़ा अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत कार्य। | 55.00 |

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते हैं।

अर्धीक्षण अभियता
लोक निर्माण विभाग
बस्तर मुडल जगदलपुर

जी-242504757/6

# महिलाओं की सत्ता में बराबरी के अधिकार की लड़ाई अभी बाकी

**अकु श्रीवास्तव**

6 दिसम्बर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने रूढ़िवाद पर आधारित महिलाओं पर बंदिश लगाने वाले कानून को खारिज किया। यह ऐतिहासिक दिन था। इसके बाद धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने वाले संविधान के अनुच्छेद 15 की महिलाओं के अधिकारों के संबंध में व्यापक व्याख्याएं हुई हैं। उक्त मुकद्दमे में याचिकाकर्त्ता थे अनुज गर्ग एवं अन्य तथा प्रतिवादी थी होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं अन्य। न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी की पीठ द्वारा पंजाब आबकारी अधिनियम-1914 की धारा 30 को चुनौती दी गई है, जो 25 वर्ष से कम आयु की महिला को किसी ऐसे परिसर में जाने से रोकती थी, जहां शराब या मादक पदार्थ का सेवन जनता द्वारा किया जाता है। इस तरह महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है। इसमें मूल अधिकार से जुड़ा 14वां अनुच्छेद भी शामिल है, जिसमें विधि के समक्ष समान संरक्षण प्राप्त है। विद्वानों का मानना है कि वैदिक काल के प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा हासिल था। हालांकि स्मृतिकाल में उनके स्तर में बदलाव आना शुरू हो गया है। चौथी शताब्दी ई.पू. के माने जाते अपस्तंभ सूत्र में नारी सुलभ आचरण संबंधी नियमों को 1730 में त्रयम्बकयज्वन ने स्त्रीधर्मपद्धति में संकलित किया था। इसका मुख्य छंद था 'मुख्यो धर्म- स्मृतिषु विहितो भार्तृशुश्रुषानाम हि-' अर्थात स्त्री का मुख्य कर्त्तव्य उसके पति की सेवा से जुड़ा है। मध्यकाल में बाहरी आक्रमणों के कारण भारतीय समाज में महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें थोपी गईं, जिसने समाज में स्त्रियों के प्रति एक बहुत ही संकुचित सोच का निर्माण किया। इस सोच से स्वतंत्रता की लड़ाई अब तक जारी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने महिलाओं के खिलाफ सती प्रथा जैसी कुरीतियों को बंद कराया। महिला अधिकारों को आज सबसे जागरूक समझे जाने वाले केरल राज्य में 18वीं-19वीं सदी में दलित स्त्रियों से बेहद बुरा बर्ताव हो रहा था। उन्हें वक्ष ढंकने की इजाजत नहीं थी। पढ़ना-लिखना मना था। उनका सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश वर्जित था और यहां तक कि उन्हें बाजारों में भी नहीं घुसने दिया जाता था। ऐसे में तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव वेगनूर में पुलाया नामक दलित समुदाय में जन्मे अय्यनकली ने दलित महिलाओं को अधिकार दिलाने और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किया। ऐसी ही समाज सुधारक और पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले ने स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, बाल विवाह और विधवा को विवाह के अधिकार के लिए आवाज उठाई और अंधविश्वासों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। सावित्री बाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। आजादी के बाद भी स्त्रियों को अधिकारों के लिए लगातार लड़ना पड़ा। सरकारी नौकरियों तथा जन प्रतिनिधित्व अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। तब जाकर वर्ष 2023 में संविधान में 106वां संशोधन किया गया। महिला आरक्षण अधिनियम नारीशक्ति वंदन पारित किया गया। इसके तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं, मगर इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं किया जा सका। यह परिसीमन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन 4 साल से लंबित पड़े जनगणना का कार्य संपन्न होने के बाद ही उसके डाटा मिलने पर संभव होगा। यदि नए साल में जनगणना का काम शुरू हो जाता है तो संभव है कि इसके पूरे आंकड़े अगले साल तक मिल जाएंगे। ऐसे में वर्ष 2026 से पहले इसके लागू होने की संभावना नहीं बन रही है। इस कानून को पारित होने के बाद भी सत्तारूढ़ दल ने इसके 2026 तक प्रभावी हो जाने का अनुमान जताया था। हालांकि तब भी विपक्ष ने 2024 में इसे लागू न करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। मगर जब 2024 के लोकसभा चुनाव और बाद में हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर तथा महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनाव हुए तो किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं को एक तिहाई टिकटें देने का साहस नहीं दिखाया।

# संसद की गरिमा का दांव पर लगना चिन्ताजनक

**ललित गर्ग**

संविधान-निर्माता भीमराव आंबेडकर को लेकर भारतीय संसद में जो दृश्य पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं, वे न केवल शर्मसार करने वाले है बल्कि संसदीय गरिमा को धुंधलाने वाले हैं। अंबेडकर को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। दोनों पक्षों ने गुरुवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथापाई भी हुई जिसमें भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी को नियमों का पालन करना पड़ेगा। संसद की मर्यादा और गरिमा सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। भारतीय संसद के प्रांगण में जिस तरह की अशोभनीय एवं त्रासद स्थिति का उत्पन्न हुई है, वे हर लिहाज से दुखद, विडम्बनापूर्ण और निंदनीय है। आरोप-प्रत्यारोप की वजह से परिवेश ऐसा बन गया है, मानो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुद्ध शत्रुता, द्वेष, नफरत की स्थितियां उग्रतर हो गई हो। और तो और, धक्का-मुक्की, दुर्व्यवहार जैसे आरोपों को लेकर पुलिस में मामला दर्ज होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इन दुखद एवं अशालीन स्थितियों का उपचार न किया गया, तो संसद में काफी कुछ अप्रिय एवं अशोभनीय होने की आशंकाएं बलशाली होगी।

कहना न होगा कि देश की संसद लोकतंत्र के वैचारिक शिखर और देश की संप्रभुता को रेखांकित करने वाला शिखर संस्थान है। इसलिए इसकी गरिमा बनाए रखना सभी सांसदों का मूल कर्तव्य बन जाता है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा होती है कि वे संसद की गरिमा को भंग न करे, अपना आचरण शुद्ध, शालीन एवं व्यवस्थित रखेंगे और व्यर्थ की बयानबाजी, धक्का-मुक्की, दुर्व्यवहार की जगह सार्थक बहस की संभावनाओं को उजागर करें। भारत की परंपरा कहती है कि वह सभा, सभा नहीं, जिसमें शालीनता एवं मर्यादा न हो। वह संसद संसद नहीं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा न करें। वह धर्म, धर्म नहीं, जिसमें सत्य न हो। वह सत्य, सत्य नहीं जो कपटपूर्ण हो। आज संसद में सांसदों का व्यवहार शर्म की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। पूरे देश की जनता ने बड़ा भरोसा जताते हुए अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजा है, ताकि वे सांसद के रूप में देश की भलाई के लिए नीति एवं नियम बनाएं, उसे लागू कराएं और जनजीवन को सुरक्षित तथा खुशहाल बनाते हुए देश का विकास करें। संसद की सदस्यता की शपथ लेते समय सांसदगण इन सब बातों को ध्यान में रखने की कसम भी खाते हैं, लेकिन उनकी कसम बेबुनियाद ही होते हुए संसद की मर्यादाओं को आहत कर रही है। बीते कुछ समय से धरना-प्रदर्शन के साथ सड़क पर राजनीतिक दमखम दिखाने वाले नजारे संसद के दोनों सदनों में भी दिखने लगे हैं। भौतिक रूप से छीना-झपटी और हाथापाई की नौबत भी दिखती रही है और विचाराधीन विषय से दूर एक-दूसरे को हीन साबित करना ही उद्देश्य बन गया है।

संसद का मूल्यवान समय बर्बाद हो रहा है, यह इससे स्पष्ट होता है कि पहली लोकसभा में हर साल 135 दिन बैठकें आयोजित हुई थीं। आज स्थिति कितनी नाजुक हो गई है, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि पिछली लोकसभा में हर साल औसतन 55 दिन ही बैठकें आयोजित हुईं। नयी लोकसभा की स्थिति तो और भी दुखद एवं दयनीय है। संसद में काम न होना, बार-बार संसदीय अवरोध होना तो त्रासद है ही, लेकिन धक्का-मुक्की तक नौबत पहुंचना ज्यादा चिन्ताजनक है। कोई भी दल हो, किसी भी दल के सांसद हो, उन्हें यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद ऐसे किसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं है। संसद और संविधान, दोनों ही सांसदों से उच्च गरिमा एवं मर्यादाओं की अपेक्षा करते हैं। संसद देश की आवाजों और दलीलों का मंच है, यह किसी भी प्रकार की शारीरिक जोर-आजमाइश का मंच न बने, इसी में देश की भलाई है, लोकतंत्र की अक्षुण्णता है। सार्थक और उत्पादक संवाद के लिए हर सांसद को संविधान का ज्ञान, संसदीय परंपराओं की जानकारी एवं उनके प्रति प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से बहुत कम सांसद ही इस ओर ध्यान देते हैं। मुखर प्रवक्ता के रूप में विपक्ष के कई सांसद अक्सर बेलगाम, फूहड एवं स्तरहीन आरोप-प्रत्यारोप दर्ज कराने में जुट जाते हैं। आधी-अधूरी सूचनाओं या गलत जानकारी के साथ विपक्ष के नेता सरकारी पक्ष को आरोपित करने में जुट जाते हैं, बयानों तो तोड़मरोड़ का प्रस्तुत करते हैं। निश्चित ही विपक्ष लगातार अपनी जिम्मेदारी से विमुख होता दिख रहा है। वह सरकार को घेरने और आरोपित करने के उद्देश्य से संसद के कार्य में अक्सर व्यवधान डालता है। लगता है विपक्ष का मकसद यही हो गया है कि संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से न चल सके और सरकार की विफलता दर्ज हो। इस तरह की विपक्ष की बौखलाहट का बड़ा कारण भाजपा की लगातार चमत्कारी जीत है।

सांसदों को समग्रता में सोचना चाहिए कि अगर संसद जोर आजमाइश एवं हिंसा का अखाड़ा होकर बात एफआईआर की राजनीति तक बढ़ेगी, तो संसद का संचालन जटिल से जटिलतर होता जायेगा। संसद में तनाव कोई नई बात नहीं है। तनाव और तल्खी का इतिहास रहा है, पर बहुत कम अवसर ऐसे आए हैं, जब शारीरिक बल का दुरुपयोग देखा गया है। संसद भवन के प्रांगण में ही नहीं, बल्कि देश में कहीं भी सांसदों को ऐसे आमने-सामने नहीं आना चाहिए, जैसे गुरुवार को देश ने देखा है। संसद भवन के प्रांगण में जगह-जगह कैमरे लगे हैं। उन कैमरों की मदद से कम से कम यह तो सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी कौन है? दुध का दुध एवं पानी का पानी हो और सच सामने आये। सच की जीत हो और झूठ नैस्तनाबूद हो। अगर किसी सांसद के सिर में चोट लगी है, तो यह वैसे भी गंभीर मसला है। भाजपा सांसद सारंगी ने यही बताया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वजह से एक व्यक्ति उनसे टकराया और वह गिर गए। ऐसा ही आरोप कांग्रेस ने भी लगाया है। पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे, पर ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सच सामने आए। यदि सच सामने न आए, तो कम से कम सभी सांसद ऐसी स्थिति फिर न बनने दें, इसके लिये संकल्पित हो।

शीतकालीन सत्र में आंबेडकर के नाम पर संसद के भीतर-बाहर जो कुछ हो रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल संसद की गरिमा से जानबूझकर खिलवाड़ करने पर तूले है। यह मानना अविश्वसनीय है कि यह धक्का-मुक्की अनजाने में हुई। राहुल गांधी आक्रामक ढंग से एक महिला सांसद के निकट जाकर उन्हें असहज करना तो बहुत ही शर्मनाक एवं कहीं अधिक फूहड़ है। पता नहीं किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उक्त घटना संसद ही नहीं, देश को भी शर्मिंदा करने वाली है। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि वह मर्यादा से विहीन दिखने लगे। ऐसी राजनीति केवल धिक्कार की पात्र होती है। संसद की मर्यादा को तार-तार करने वाली ऐसी घटनाएं सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती कटुता का ही नतीजा है, जो देश के हित में नहीं है। पक्ष-विपक्ष के बीच बढ़ती शत्रुता न केवल भारतीय राजनीति बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक हैं। दोनों पक्षों के बीच शत्रु भाव कम होने के कोई आसार इसलिए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दे सतह पर लाए जा रहे हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं बनता और जिनका मकसद लोगों को बरगलाना एवं गुमराह करना है। बीते कुछ समय से यह जो भय का भूत खड़ा किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, वह राजनीति के छिछले स्तर का ही परिचायक है। कोई बताये तो संविधान कब और कैसे खतरे में आ गया। संसद में ऐसे विषयों को लेकर सार्थक एवं सौहार्दपूर्ण संवाद हो, वाद-विवाद की जगह कटुता न ले, विमर्श और विचार की गंभीरता से ही लोकतंत्र की शक्ति बढ़ेगी। दलगत पसंद और नापसंद स्वाभाविक है, किंतु उससे ऊपर उठकर रचनात्मक भूमिका निभाने का साहस भी जरूरी है।

**पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय**

## वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

**( गतांक से आगे... )**

यथा- तत्राभवद्भगवान्व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्ष्य:। अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो, वृतस्त्रिवालैरवधूतवेश:।। तं द्वचष्टवर्ष सुकुमारपाद-करोरुबाह्व सकपोलगात्रम् । अर्थात् इसी अवसर में निष्काम विचरते हुये अलक्षित शरीर वाले आत्मसन्तुष्ट अवधूत-वेषधारी व्यासपुत्र शुकदेव जी आये, जो सोलह वर्ष के बालक विदित होते थे। उनके चरण, कर, उरु, भुजा, सुकोमल कपोल एवं सब अङ्ग परम मनोहर थे। शुकदेव जी को देखकर सब ऋषि मुनि अपने 2 आसनों से उठे तथा राजा ने शुकदेव जी का पूजन करके कहा- मालूम होता है कि श्रीकृष्ण भगवान् ही मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि - अन्यथा तेऽव्यक्तगतेर्दर्शनं न: कथं नृणाम्। (भा0 1।16।36) अर्थात् - यदि ऐसा न होता तो जिनकी गति (चलना फिरना) अव्यक्त (प्रत्यक्ष नहीं) उन आप जैसे मुक्तपुरुष का दर्शन हम मनुष्यों को क्योंकर हो सकता है? उपर्युक्त श्लोकों में अलक्ष्यलिङ्ग और अव्यक्तगति: आदि विशेषणों से शुकदेव जी को पांचभौतिक शरीर- घारी मनुष्यों से विलक्षण दिव्यदेह-सम्पन्न कहा है। योगी लोग स्वेच्छ। से मुमुक्षुजनों के हितार्थ दर्शन दिया करते हैं। वे संकल्प-मात्र से जिस लोक में जिस रूप में जब चाहें जा सकते हैं। इसलिए दिव्यगुणोपेत, परमयोगी शुकदेव जी का स्वेच्छा से लोका- न्तरचारी होने के कारण राजा परीक्षित के प्रति श्रीमद्भागवतपुराण सुनाना सुसंभव है और इस तरह महाभारत तथा भागवतलिखित वर्णनों की एकवाक्यता होने से दोनों ही ग्रंथ श्रीव्यासजी के बनाये हुये सिद्ध हैं। (6) सब विद्वान् मानते हैं कि अठारह पुराण महाभारत के बाद बनाये गये हैं, क्योंकि पुराणों में तो महाभारत का नाम आता है, परन्तु महाभारत में पुराणों का नाम नहीं आता। इसलिए महाभारत का निर्माता पुराणों का कर्ता सिद्ध नहीं होता।

**क्रमश: ...**

# 'राष्ट्रीय गणित दिवस': संख्याओं के जादूगर थे श्रीनिवास रामानुजन

**योगेश कुमार गोयल**

प्रतिवर्ष 22 दिसम्बर को भारत में 'राष्ट्रीय गणित दिवस' मनाया जाता है, जो देश के महान् गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन को सम्मान देने के उद्देश्य से उनकी स्मृति में उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। करीब एक दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने चेन्नई में रामानुजन की 125वीं जयंती समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि ऐसे प्रतिभावान तथा गूढ़ ज्ञान वाले पुरूषों और महिलाओं का जन्म कभी-कभार ही होता है। गणित में रामानुजन के अविस्मरणीय योगदान को याद रखने और सम्मान देने के लिए उसी अवसर पर रामानुजन के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 22 दिसम्बर को 'राष्ट्रीय गणित दिवस' मनाए जाने का निर्णय लिया गया था।

मद्रास से करीब चार सौ किलोमीटर दूर तमिलनाडु के ईरोड शहर में 22 दिसम्बर 1887 को जन्मे श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का बचपन कठिनाइयों और निर्धनता के दौर में बीता था। तीन वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे और तब परिवार के लोगों को चिंता होने लगी थी कि कहीं वह गूंगे न हों लेकिन कौन जानता था कि यही बालक गणित के क्षेत्र में इतना महान् कार्य करेगा कि सदियों तक दुनिया उन्हें आदर-सम्मान के साथ याद रखेगी। उन्हें गणित में इतनी दिलचस्पी थी कि गणित में उन्हें प्राय: सौ फीसदी अंक मिलते थे लेकिन बाकी विषयों में बामुश्किल ही परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते थे क्योंकि गणित के अलावा उनका मन दूसरे विषयों में नहीं लगता था। उन्होंने कभी गणित में किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं लिया था।

गणित में अतुलनीय योगदान के लिए श्रीनिवास रामानुजन को के. रंगनाथ राव पुरस्कार भी दिया गया था। उनका गणित प्रेम इतना बढ़ गया था कि उन्होंने दूसरे विषयों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। दूसरे विषयों की कक्षाओं में भी वे गणित के ही प्रश्नों को हल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित के अलावा दूसरे सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए और इस कारण उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद हो गई। परिवार की आर्थिक हालत पहले ही ठीक नहीं थी, इसलिए परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने गणितज्ञ रामास्वामी अय्यर के सहयोग से मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी करनी शुरू की। नौकरी के दौरान भी वे समय मिलते ही खाली पन्नों पर गणित के प्रश्नों को हल करने लग जाया करते थे।

एक दिन एक ब्रिटिश की नजर उनके द्वारा हल किए गए गणित के प्रश्नों पर पड़ी तो वह उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। उसी अंग्रेज के माध्यम से रामानुजन का सम्पर्क जाने-माने ब्रिटिश गणितज्ञ और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एच हार्डी से हुआ। हार्डी ने उनकी विलक्षण प्रतिभा को भांपकर उन्हें अपनी प्रतिभा को साकार करने के लिए लंदन बुला लिया और उनके लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में व्यवस्था की, जिसके बाद उनकी ख्याति दुनियाभर में फैल गई। जी. एस. हार्डी ने रामानुजन को यूलर, गोस, आर्किमिडीज, आईजैक न्यूटन जैसे दिग्गजों के समकक्ष श्रेणी में रखा था।

# हिन्दू कोड बिल को लेकर नेहरू सरकार से अलग हुए थे अम्बेडकर

**जयसिंह रावत**

संविधान पर बहस हो और बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में संविधान पर काफी बहस हुई तो डॉ. अम्बेडकर का नाम आना स्वाभाविक ही था। चर्चा के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृहमंत्री अमित शाह द्वारा डॉ. अम्बेडकर और कांग्रेस तथा खासकर जवाहर लाल नेहरू के बीच संबंधों का मामला जोरदार ढंग से उठाया गया। दोनों सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं की बात वास्तव में काफी हद तक सही थी।

दरअसल, अगर बाबा साहेब के संबंध कांग्रेस और नेहरू सरकार से अच्छे होते तो वह 1951 में सरकार से इस्तीफा क्यों देते? अगर उनके कांग्रेस से संबंध अच्छे होते तो वह यह पार्टी क्यों छोड़ते? यह भी सच ही था कि संविधान निर्माता ने जब 1952 में उत्तरी बम्बई से अपनी ही पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडेरेशन की ओर से आजाद भारत का पहला चुनाव लड़ा तो वह कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सदोबा काजरोल्कर से हार गये थे। कांग्रेस प्रत्याशी भी दलित ही थे। लेकिन इस सच्चाई से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि उनके जितने गहरे और बुनियादी मतभेद जनसंघ और आरएसएस से थे उतने कांग्रेस से नहीं थे।

बाबा साहेब का सचमुच नेहरू सरकार से मोह भंग हो गया था। डॉ. अंबेडकर का नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण हिंदू कोड बिल पर असहमति थी। इस बिल का उद्देश्य महिलाओं के लिए सम्पत्ति के अधिकार, विवाह और तलाक संबंधी कानूनों में सुधार लाना था। अंबेडकर समाज में महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और इस बिल को एक ऐतिहासिक कदम मानते थे। उन्होंने इस बिल को एक ''सामाजिक क्रांति'' के रूप में देखा था।

हालांकि, नेहरू को इस बिल का समर्थन था, लेकिन उनके अपने वरिष्ठतम सहयोगी सरदार पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और के.एम. मुंशी आदि इस बिल के पक्ष में नहीं थे, इसलिए नेहरू इसे संसद में तत्काल पास कराने के पक्ष में नहीं थे। वैसे भी यह एक संवेदनशील सामाजिक और धार्मिक मुद्दा था और उन्हें हिंदू समाज में विद्यमान परंपराओं और प्रथाओं के खिलाफ सीधी चुनौती का डर था।

इसके अलावा नेहरू इसे धीरे-धीरे लागू करने के पक्षधर थे, ताकि समाज इसे स्वीकार सके। आखिर हुआ भी यही हिन्दू कोड बिल 1955 और 1956 में चार खण्डों में पारित कराया गया। अंबेडकर का यह मानना था कि हिंदू कोड बिल में सुधारों को जल्द और प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। जबकि नेहरू सरकार इस पर ढीले रुख अपनाए हुए थी। इसके चलते उनके बीच असहमति बढ़ी। जब अंबेडकर को यह महसूस हुआ कि नेहरू और उनकी सरकार इस बिल को लागू करने में संजीदा नहीं हैं, तो उन्होंने 1951 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि कैबिनेट में रहते हुए अंबेडकर और नेहरू के बीच का तनाव बढ़ता गया, खासकर सामाजिक सुधारों और कानूनी बदलावों को लेकर। अंबेडकर ने महसूस किया कि उनका काम और उनकी नीतियों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था। इससे उनका विश्वास कमजोर हो गया कि वे कैबिनेट के भीतर अपने एजेंडे को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। स्वयं दलित होने का अभिशाप झेल चुके अंबेडकर का दृष्टिकोण राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के प्रति बहुत कट्टर था।

वे मानते थे कि हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, खासकर दलितों और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में। जबकि नेहरू की नीति अधिक उदारवादी और प्रगतिशील थी। वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को लेकर ज्यादा सतर्क थे। अंबेडकर का यह विश्वास था कि सरकार समाज में सुधारों को लागू करने के मामले में पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाई थी, जो उनके दृष्टिकोण से जरूरी था।

डॉ. अंबेडकर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू से जटिल और विवादित रिश्ता था। उनका जीवन कांग्रेस के साथ कई मोड़ों पर जुड़ा और अलग हुआ। अंबेडकर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संबंध शुरू में सहयोगात्मक था, लेकिन समय के साथ उनके विचारों में असहमति बढती गई। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए उपेक्षापूर्ण समझा और अंतत: कांग्रेस से अलग होकर अपने लिए एक स्वतंत्र मार्ग चुना।

अंबेडकर ने यह महसूस किया कि कांग्रेस की प्राथमिकताएँ दलितों और समाज के निचले वर्गों के लिए पर्याप्त नहीं थीं। प्रारंभ में अंबेडकर का कांग्रेस के साथ संबंध सकारात्मक था। 1919 में जब रियासतों और विभिन्न जातियों के बीच समानता की बात उठाई जा रही थी तो अंबेडकर ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश की थी।

हालांकि, उनका मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों की रक्षा पर था और कांग्रेस का ध्यान स्वाधीनता पर केन्द्रित था। अंबेडकर को लगता था कि कांग्रेस मुख्य रूप से उच्च जातियों और हिन्दू समाज के हितों की रक्षा कर रही है, और दलितों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। उनका मानना था कि कांग्रेस की नीतियाँ हिन्दू धर्म के भीतर सुधार करने की बजाय केवल स्वाधीनता प्राप्ति की ओर केंद्रित थीं।

डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्रीय सवयं सेवक संघ (आरएसएस) के साथ रिश्ते और भी खराब थे। कांग्रेस और नेहरू मंत्रिमण्डल से अलग होना जिस तरह डॉ. अम्बेडकर और कांग्रेस के नकारात्मक रिश्तों का प्रमाण है उसी तरह उनका हिन्दू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाना और खुल कर अपने भाषणों और पुस्तकों में हिन्दू धर्म की आलोचना करना उनके आरएसएस और भाजपा की मूल संस्था जनसंघ के साथ कड़ुवे रिश्तों का भी प्रमाण माना जा सकता है। कांग्रेस के प्रति उनकी नाराजगी थी और हिन्दूवादी आरएसएस और जनसंघ के प्रति उनका घोर नकारात्मक रिश्ता रहा।

अंबेडकर ने आरएसएस के विचारों और उद्देश्य की खुलकर आलोचना की। उनका मुख्य आरोप था कि यह संगठन हिन्दू धर्म के जातिवादी ढांचे को बढ़ावा देता है और हिन्दू समाज में सुधार के बजाय उसमे असमानता और भेदभाव को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने हिन्दू राष्ट्र की सोच वालों को भारतीय समाज में वास्तविक सुधार और समानता के लिए खतरे के रूप में देखा।

अंबेडकर के लिए, आरएसएस और इसके विचारों के बावजूद समाज में जातिवाद और भेदभाव का अंत तभी संभव था, जब हिन्दू धर्म को बुनियादी रूप से बदल दिया जाए, जो कि आरएसएस की दृष्टि नहीं थी। डॉ. अंबेडकर ने अपनी किताब ''थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट'' में स्पष्ट किया था कि उन्होंने हिन्दू धर्म में कोई भी सुधार की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उनकी राय में आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन हिन्दू धर्म को बचाने के लिए काम कर रहे थे, जबकि यह धर्म खुद जातिवाद और असमानता से भरा हुआ था। उनका यह मानना था कि इन संगठनों के विचारों के चलते हिन्दू धर्म के भीतर कोई सुधार संभव नहीं था और समाज में सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी और असंवेदनशील थी।

## आज का इतिहास

1910 अमेरिका में पहली बार डाक बचत पत्र जारी।
1920 सोवियत संघ की 8 वीं कांग्रेस ने GOELRO योजना को मंजूरी दे दी, जो राष्ट्रीय आर्थिक सुधार और विकास के लिए पहली योजना थी।
1937 लिंकन टनल, न्यू यॉर्क सिटी को वेहेवकेन, न्यू जर्सी से जोड़ता हुआ, खुल गया।
1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के जनरल एंथोनी मैकऑलिफ ने एंगल शब्द के साथ युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण के जर्मन अल्टीमेटम का जवाब दिया, 'NUTS!'
1947 इटली ने नए संविधान को स्वीकार करने के लिए वोट किया।
1947 इतालवी गणराज्य के संविधान को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था।
1956 ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र की बंदरगाह पोर्ट सईद पर 50 दिन तक अतिग्रहण जारी रखने के बाद इस बंदरगाह को छोड़ दिया और अपनी सेना को मिस्र से वापस बुला लिया।
1964 लॉकहीड एसआर -71 ब्लैकबर्ड , संयुक्त राज्य एयरफोर्स की लंबी दूरी की, मच 3+ रणनीतिक टोही विमान और द वर्ल्ड की सबसे तेज हवा से चलने वाले मानवयुक्त विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी।
1972 ऑस्ट्रेलिया ने चीन और पूर्वी जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया।
1972 निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में आए 6.25 तीव्रता के भूकंप में 12 हजार से अधिक लोग मारे गए।
1974 ग्रांडे कोमोर, अंजून और मोहाली ने कोमोरोस के भरोसेमंद देश बनने के लिए मतदान किया।
1984 न्यूयॉर्क सिटी सबवे ट्रेन की सवारी करते समय, बर्नहार्ड गोएट्ज ने चार अफ्रीकी अमेरिकी युवकों को गोली मार दी, जिन्होंने उसे लूटने का प्रयास किया, सतर्कता, नस्लवाद और आत्मरक्षा की कानूनी सीमाओं पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई।
1988 ब्राजील के संघचालक और पर्यावरण कार्यकर्ता चिको मेंडेस को उनके Xapuri घर में रखा गया था।
1988 स्कॉटलैंड की सीमा के नजदीक लॉकरबी शहर में एक पैन एम का जंबो जेट 258 यात्रियों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
1997 हुसैन फ़राह ऐदिद ने सोमालिया के पूर्वजन्म के विवादित शीर्षक को त्याग दिया।
2001 उत्तरी गठबंधन के बुरहानुद्दीन रब्बानी ने हामिद करजई के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को पॉवरिन अफगानिस्तान सौंप दिया।

# बहुसंख्यकों की बात को हिन्दुओं की आवाज बताना सुनियोजित साजिश

**संजय सक्सेना**

विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव द्वारा दिया गया संबोधन जज साहब के लिये गले की फांस बन गया है। दरअसल, 8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। वायरल वीडियो में उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन का समर्थन किया और कहा कि कानूनों को बहुसंख्यकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा,'ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। आप यह भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जस्टिस होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भइया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए,समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होते हैं, जो कहते हैं उसी को माना जाता है। जज साहब के इस बयान पर सियासी हो-हल्ला हुआ यह तो समझ में आता है लेकिन बड़ी अदालत यदि ऐसे किसी बयान को हिन्दुओं से जोड़कर कोई कदम उठाये तो समझ से परे हैं। जज शेखर यादव ने गलत नहीं कहा था कि कानून बहुसंख्यकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। यदि जज साहब गलत हैं तो फिर हमारा लोकतंत्र कैसे सही हो सकता है,यह लोकतंत्र ही है जिसके अनुसार जब देश प्रदेश से लेकर गांवों तक में चुनाव होता है तो बहुसंख्यकों के वोट हासिल करके ही सरकार बनती है, जिसमें सभी समाज और धर्म के मतदाता शामिल होते हैं।यहां तक की कोर्ट की बहु सदस्यीय बेंच जब किसी मामले पर फैसला सुनाती है तो भी यही होता है। इसको एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। नवंबर 2019 में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने बहुमत से फैसला सुनाया था।इसी को बहुसंख्यक कहा जायेगा। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जज शेखर यादव को तलब कर लिया है। यह कॉलेजियम जिस न्यायाधीश के खिलाफ किसी विवादास्पद मुद्दे पर हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगती है तो उन्हें मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि जस्टिस शेखर कुमार यादव को न्यायिक नीति की सीमा पार करने के आरोपों के खिलाफ अपना पक्ष रखने का मौका मिल सकता है।

खैर, विवादों में घिरे जज शेखर यादव का साथ मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि जज साहब ने कुछ गलत नहीं बोला। हॉ योगी साहब ने अपनी बात कहते हुए राजनैतिक फायदे नुकसान का भी ध्यान रखा। इसी के सहारे योगी ने एक बार फिर हिंदुत्व यानि बहुसंख्यक समाज के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष को आईना दिखाया। उन्होंने हिंदू एकता, न्यायमूर्ति शेखर यादव और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के रवैये पर तीखा हमला किया। सीएम ने खुले मंच से न्यायमूर्ति के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बहुसंख्यक समाज को मजबूत करने की बात करने वालों को अब धमकी दी जा रही है। भारत की विरासत के संवर्धन की बात विपक्ष को इतनी खलती है कि वह महाभियोग ले आते

हैं। सीएम ने जनता से सच को दबाने वाले, संविधान का गला घोंटने वाले ऐसे दलों के लोगों की मानसिकता को उजागर करने की अपील की। योगी ने पहले मुंबई और फिर लखनऊ के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और न्यायमूर्ति के मुद्दे पर खुले मंच से अपनी बात रखी है। सीएम ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग भारत का ठेका लेकर घूमते हैं और डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। वे संविधान के नाम पर पाखंड कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर फैसला देने वाले जजों को आज तक धमकी मिल रही है। ऐसे ही विपक्ष राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। विपक्ष को यह बात खल रही है कि किसान का पुत्र इस पद पर कैसे पहुंच गया। एक न्यायमूर्ति अगर एक नागरिक के रूप में सच्चाई को रखते हैं तो महाभियोग लाकर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है।

योगी ने गलत नहीं कहा कि देश में हर हाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होना चाहिए। दुनिया में बहुसंख्यक समाज जो कहता है, व्यवस्था वैसे संचालित होती है। भारत की मंशा है कि अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक का भेद समाप्त हो और सब लोगों पर समान कानून लागू होना चाहिए लेकिन विपक्ष को यह बात अच्छी नहीं लग रही है। ये लोग संविधान का गला घोंटकर जबरन अपने दम पर देश की व्यवस्था चलाना चाहते हैं। दबंगई से सच को दबाने की कोशिश करने वालों को एक्सपोज किए जाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने जज शेखर यादव के बयान के सहारे अपनी बात को सही साबित करने के लिये यह भी कहा कि संभल में 46 साल पहले जिनके(कांग्रेस)शासनकाल में जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वह मंदिर फिर से सबके सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि 46 वर्ष पहले जिन दरिंदों ने संभल के अंदर नरसंहार किया था, उन्हें आज तक सजा क्यों नहीं मिली। संभल में जिनकी निर्मम हत्या हुई, उन निर्दोषों का क्या कसूर था। जो भी सच बोलेगा, उसे धमकी दी जाएगी, यह लोग उसका मुंह बंद कराने का प्रयास करते हैं।

जज शेखर यादव के ऊपर सबसे अधिक हमला टुकड़े-टुकड़े गैंग द्वारा किया जा रहा है,जो बहुसंख्यकों की आवाज को हिन्दुओं की आवाज बताने का प्रोपोगंडा करते हैं। वकील और कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने सीजेआई से इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण की इन-हाउस जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि जज ने न्यायिक नैतिकता और निष्पक्षता और पंथनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया।उधर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आठ दिसंबर को माकपा नेता वृंदा करात ने भी चिट्ठी लिखकर जस्टिस यादव के भाषण को उनकी शपथ का उल्लंघन बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की मांग की। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बयान की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज से अपने बयान वापस लेने और माफी मांगने के लिए कहा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी जज शेखर यादव के बयान से आग बबूला हैं। कुल मिलाकर बहुसंख्यक का मतलब सिर्फ हिन्दू और अल्पसंख्यक का अर्थ सिर्फ मुसलमान होने तक नहीं सीमिति किया जा सकता है। बहुसंख्यक शब्द व्यापक है। बहुसंख्यक आबादी यदि यह कहती है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मिले, देश में महंगाई, भ्रष्टाचार कम हो, सबको रहने के लिये छत और भोजन मिले तो इसे हिन्दुओं की बात नहीं कहा जायेगा, यह देश की बहुसंख्यक आबादी की आवाज होगी।

# संसद परिसर में सांसद का रक्त गिरना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं

**नीरज कुमार दुबे**

अक्सर कुर्ते की बाहें चढ़ा कर विरोधी दलों पर हमला बोलने वाले राहुल गांधी ने आज जिस तरह संसद में भाजपा सांसदों के साथ बर्ताव किया वह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बन गया। संयोग देखिये कि यह सब तब हुआ जब हाल ही में संसद ने %भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा% पर चर्चा की। देखा जाये तो यह कांग्रेस का दोमुंहापन नहीं तो और क्या है कि एक ओर उसके सांसद जय भीम के नारे लगा कर प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी ओर पार्टी के नेता संविधान और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गुंडागर्दी पर उतर रहे थे। बात-बात पर संविधान की प्रति दिखाने वाले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उसमें कहां

लिखा है कि संसद में या संसद परिसर में हिंसा की जाये या किसी को धक्का दिया जाये? दिन-रात संविधान की प्रति दिखाने वाले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि संविधान में कहां लिखा है कि महिला सांसद के साथ बदतमीजी की जाये? राहुल गांधी ने आज जो कुछ किया है वह सब देश के सामने है। देश को निर्णय लेना ही होगा कि संसद में उसे कैसे प्रतिनिधि चाहिए? जनता के लिए सरकार से भिड़ना अलग बात है लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी के साथ हिंसा करना अलग बात है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराई गयी है। देखना होगा कि उनके खिलाफ जांच में क्या निकल कर आता है लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने विपक्ष के नेता पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। इतिहास उन्हें विपक्ष के ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जिसने मर्यादाओं और लोकतांत्रिक परम्पराओं की कभी परवाह नहीं की। देखा जाये तो भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का सिर्फ माथा नहीं फूटा है बल्कि उनका जो रक्त संसद परिसर में गिरा है उससे लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को बड़ी ठेस पहुँची है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। बहरहाल, आज की घटना यह भी दर्शाती है कि भविष्य में सांसदों को राहुल गांधी से सचेत रहने की जरूरत है। वैसे तो संसद में अब तक माइक तोड़ने, पर्चे फाड़ने या शोर मचाने जैसे वाकये सामने आते थे लेकिन अब जिस तरह धक्का मुक्की होने लगी है उसने भारत की संसदीय प्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया है। सोनिया गांधी चूंकि विपक्ष की नेता रही हैं इसलिए उन्हें अपने पुत्र को समझाना चाहिए कि मुद्दों का हल हिंसा से नहीं वार्ता और चर्चा से निकलेगा। निश्चित ही आज वायनाड और रायबरेली के मतदाता भी पश्चाताप कर रहे होंगे कि उन्होंने क्यों राहुल गांधी की बातों पर विश्वास करके उन्हें चुन लिया।

# क्या अडानी पर लगे आरोप वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को कमजोर करेंगे

**रवि दत्ता मिश्रा**

सितंबर में भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आई.पी.ई.एफ.) के फेयर इकोनॉमी स्तंभ पर हस्ताक्षरकर्त्ता बन गया है, जो अनिवार्य रूप से सभी 15 व्यापार भागीदारों को भ्रष्टाचार, जिसमें रिश्वतखोरी भी शामिल है, को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए बाध्य करता है। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और 7 अन्य पर 250 मिलियन डॉलर के रिश्वत मामले में अमरीका द्वारा अभियोग लगाए जाने से नई दिल्ली को अमरीका सहित किसी भी भागीदार की जांच का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार को एक प्रैस ब्रीफिंग के दौरान अडानी के अभियोग और आई.पी.ई.एफ. में भारत की स्थिति पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा, ''हमने वही प्रतिबद्धताएं ली हैं जो अन्य सरकारों ने आई.पी.ई.एफ. स्तंभ में ली हैं। देश में जो भी कानून है, उसका पालन किया जाएगा।''

भारत और अमरीका सहित 14 अन्य व्यापार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्पक्ष अर्थव्यवस्था स्तंभ समझौते के तहत, भारत ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार (जिसमें रिश्वतखोरी भी शामिल है) और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध पूरे भारत-प्रशांत क्षेत्र में समृद्ध, समावेशी और स्थिर आर्थिक व्यवस्था की नींव को नष्ट करते हैं। सदस्य देशों ने भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को लागू करने और प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों ने कहा कि अभियोग सदस्य देशों को परामर्श के लिए बुलाकर कई मुद्दों पर भारत पर दबाव बनाने की अनुमति देता है।

समझौते में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि किसी भी समय किसी पक्ष को इस समझौते के किसी प्रावधान के दूसरे पक्ष के कार्यान्वयन के बारे में चिंता है, तो संबंधित पक्ष लिखित अधिसूचना के माध्यम से परामर्श का अनुरोध कर सकता है। एक व्यापार विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अमरीकी कानून, विशेष रूप से विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफ.सी.पी.ए.), अमरीका में कारोबार करने वाली अमरीकी और गैर-अमरीकी दोनों

संस्थाओं पर लागू होता है, जिसमें वित्तपोषण जुटाना भी शामिल है। हालांकि, आई.पी.ई.एफ. समझौता सदस्य देशों पर भ्रष्टाचार को रोकने और उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए कदम उठाने का दायित्व डालता है।

विशेषज्ञ ने कहा, ''आई.पी.ई.एफ. के किसी भी समझौते के पीछे यह दृष्टिकोण था कि औपचारिक विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परामर्श चैनलों के माध्यम से कार्रवाई शुरू की जा सकती है। हालांकि इसे अभी पूरी तरह से चालू किया जाना बाकी है, लेकिन चर्चा शुरू करने और भारत पर दबाव डालने की पर्याप्त गुंजाइश है।'' अडानी समूह ने आरोपों को 'निराधार' बताते हुए उनका खंडन किया है। आई.पी.ई.एफ. के तहत राज्य जवाबदेह हैं । निष्पक्ष अर्थव्यवस्था स्तंभ पार्टियों को 'व्यापार प्राप्त करने या बनाए रखने' या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्य अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए 'रिश्वतखोरी को अपराध बनाने' के लिए भी प्रोत्साहित करता है। समझौते में कहा गया है कि पार्टियां मानती हैं कि यदि कोई उम्मीदवार सार्वजनिक पद ग्रहण करता है तो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से रिश्वत देना सुशासन को कमजोर करता है। प्रत्येक पार्टी भ्रष्टाचार अपराधों को रोकने और उनका समाधान करने के लिए कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

क्लैरस लॉ एसोसिएट्स की पार्टनर आर.वी. अनुराधा ने कहा, ''आई.पी.ई.एफ. फेयर इकोनॉमी समझौता अमरीका और भारत सहित अन्य देशों के बीच है, जिसके तहत प्रत्येक पार्टी ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराधों को संबोधित करने और कर प्रशासन में सुधार करने के लिए दायित्व लिया है।'' उन्होंने आगे कहा कि समझौते के तहत राज्य एक-दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं। यदि कोई पक्ष दूसरे पक्ष के दायित्वों के क्रियान्वयन के बारे में 'चिंता' जताता है, तो ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए यदि अमरीका द्वारा कहा जाता है, तो भारत को परामर्श में शामिल होने की आवश्यकता होगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफैसर बिस्वजीत धर ने कहा, ''रिश्वत मामले का निहितार्थ यह है कि आई.पी.ई.एफ.. सदस्य हम पर अपने कानूनों में संशोधन करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। वैश्वीकृत दुनिया में, आपको घरेलू कानूनों को वैश्विक नियमों के साथ जोडऩा होगा।''

धर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प के व्हाइट हाऊस की कमान संभालने के साथ, इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल बातचीत में भारत के खिलाफ किया जा सकता है। धर ने कहा, ''अगर हमें लगता है कि हम बहुपक्षीय समझौतों से सरकारी खरीद को बाहर करके इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबा सकते हैं, तो हम गलत हैं। वैश्विक नियमन में सुधार हो रहा है, और भारत को दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए तालमेल बनाए रखना होगा।''अमरीकी अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजों के अनुसार, गौतम अडानी, उनके भतीजे और 6 अन्य पर आंध्र प्रदेश सरकार के एक उच्च पदस्थ अधिकारी को लगभग 1,750 करोड़ रुपए (लगभग 228 मिलियन डॉलर) की रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है।

# भाजपा के खिलाफ एकजुट दिखाई दिया विपक्ष

**राहिल नोरा चोपड़ा**

कांग्रेस की महत्वपूर्ण चुनावी हार के मद्देनजर, सहयोगी दल सत्ता समीकरणों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पार्टी से गठबंधन में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को सही ठहराने के लिए कहा है, न कि इसे हल्के में लेने के लिए। जबकि टी.एम.सी. प्रमुख ममता बनर्जी ने इस पद को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाया है और शरद पवार और लालू प्रसाद जैसे क्षत्रपों का समर्थन प्राप्त कर 'इंडिया' ब्लॉक का नेतृत्व किया है।

समाजवादी पार्टी ने भी यू.पी. उप-चुनावों में अपनी ताकत दिखाई है और अब उसने दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला किया है, जिन्हें कांग्रेस चुनौती दे रही है। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व विचारक और स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग की। उनकी हिंदुत्व साख को पुनः प्राप्त करने का प्रयास राहुल गांधी के सावरकर के खिलाफ लगातार अभियान के बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस ने अडानी विवाद जैसे मुद्दों पर सहयोगियों के साथ खुद को अलग पाया है, जिसमें टी.एम.सी. और सपा ने भी उसका साथ दिया है।

विपक्ष ने पार्टी लाइन से हटकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। उन पर राज्यसभा में अपने बयान में डा. बी.आर. आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा और आर.एस.एस.पर आंबेडकर के योगदान को कमतर आंकने का आरोप लगाया। जबकि 'आप' सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने तेदेपा प्रमुख एन.चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखे। दोनों भाजपा के प्रमुख सहयोगी हैं। केजरीवाल ने शाह पर 'लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने' का आरोप लगाया और दोनों नेताओं से भाजपा के साथ अपने गठबंधन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

शाह के बयानों को सुर्खियों में रखकर, उन्होंने प्रभावी रूप से भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में लाने के लिए मजबूर कर दिया है, जो संसद में दुर्लभ है जहां सत्तारूढ़ दल अक्सर बहस की शर्तें तय करता है। एक बार फिर विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट दिखाई दिया है।

**2027 के यू.पी. विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस :** कांग्रेस द्वारा राज्य कार्यकारिणी, जिला, शहर और ब्लॉक इकाइयों को भंग करने का फैसला पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए जरूरी पहला कदम है, ताकि इसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए तैयार किया जा सके। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे उसकी मौजूदगी बढ़ेगी और गठबंधन की बातचीत में अहम भूमिका भी निभाएगी। पार्टी यह भी चाहती है कि भविष्य में सहयोगियों के साथ बातचीत के दौरान अलग-अलग मजबूत सीटों पर अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए और जगह मिल सके। चर्चा है कि कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष अजय राय, जिन्हें प्रियंका गांधी की आंख और कान माना जाता है, को पदोन्नत कर ए.आई.सी.सी. में भेजा जाएगा। राय भूमिहार जाति से आते हैं, जो पूर्वी यू.पी. में एक छोटी आबादी है, जिसका मुश्किल से 5 संसदीय क्षेत्रों में प्रभाव है। चर्चा है कि गांधी परिवार के बेहद भरोसेमंद सहयोगी और अमेठी से सांसद के.एल. शर्मा को यू.पी. कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

किशोरी लाल शर्मा 1984-85 से गांधी परिवार के लिए अमेठी के मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं, जिससे उन्हें यू.पी. कांग्रेस की पूरी समझ है। इसके अलावा, उन्होंने नई दिल्ली में महादेव रोड पर एक कार्यालय स्थापित किया है, जहां यू.पी. कांग्रेस के शिकायतकर्त्ता अक्सर आते हैं। शर्मा सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने का काम करते हैं।

**दिल्ली के मुद्दे उठाएंगे वामपंथी दल :** वामपंथी दल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अपील की है कि 'इंडिया' ब्लॉक को मिलकर चुनाव लडऩा चाहिए। गुरुवार को एक प्रैस कांफ्रैंस में वामपंथी दलों ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादे के साथ एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। जबकि दिल्ली नगर निगम का विकेंद्रीकरण, शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण और बेरोजगारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम मासिक मजदूरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए करना, पेयजल जैसे मुद्दे वामपंथी दल उठाएंगे।

सी.पी.आई. (एम) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वकील अशोक अग्रवाल और जगदीश चंद को क्रमशः करावल नगर और बदरपुर से मैदान में उतारा है। सी.पी.आई. (एम.एल.) ने 2 सीटों पर चुनाव लडऩे की योजना बनाई है। नरेला से उसने अनिल कुमार के नाम की घोषणा की है, जबकि कोंडली सीट के लिए अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सी.पी.आई. ने विकास पुरी से शेजौ वर्गीस और पालम सीट से दलीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है।

**महाराष्ट्र भर में दौरा करेंगे ओ.बी.सी. नेता छगन भुजबल :** 77 वर्षीय ओ.बी.सी. नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र भर में दौरा करने और लोगों से बातचीत करने का फैसला किया है और यहां तक कि इसी तरह का रास्ता अपनाने का संकेत भी दिया है। उन्होंने अपनी खास नाटकीय शैली में कहा, ''जहां नहीं चैना, वहां नहीं रहना।'' उन्होंने एन.सी.पी. अध्यक्ष और उप-मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा नई महायुति कैबिनेट में जगह न दिए जाने पर निराशा व्यक्त की, लेकिन दावा किया कि भाजपा के सी.एम. देवेंद्र फड़णवीस वास्तव में उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। भुजबल ने कथित तौर पर पार्टी को अपनी मर्जी से चलाने के लिए अजित की आलोचना भी की। राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है, जो उभरती स्थिति पर भुजबल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है।

# बांग्लादेश पर अराकान आर्मी का हमला भारत के सामने सुनहरा अवसर

**जगदीश यादव**

बांग्लादेश एक भीषण संकट से घिर गया है। उसे उसकी औकात पता चल गई है। बांग्लादेश जिस वक्त भारत को धमकी देने में व्यस्त था और अपने देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर मौन था ठीक उसी वक्त उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा कर लिया है। वहां रॉकेट लांचर और ड्रोन से भी भीषण हमले की बात कही जा रही है। यानी बड़बोले बांग्लादेश की हालात अभी खुद को सुरक्षित करने में है। क्यों की अराकान आर्मी के हमले के बाद वहां की जनता में दहशत है। आरोप लगाया जा रहा है कि उक्त हमले भारत के संकेत पर किए जा रहे है। बांग्लादेश के हालात तो यह है कि, वहां राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ, अब देश की सीमाएं भी खतरे में आ गई हैं। म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी (एए) ने बांग्लादेश के टेकनाफ क्षेत्र के तमाम हिस्सों पर कब्जा कर कर दना दन हमले कर रही है। बांग्लादेश में इन दिनों कट्टरपंथियों के बढ़ गए वर्चस्व के कारण स्थानीय मीडिया भी मौन है। बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा पर अराकान आर्मी और बांग्लादेशी बलों के बीच लगातार गोलीबारी हुई है। हालात तो यह है कि सीमा के करीब बांग्लादेशी आर्मी मैदान छोड़कर भाग खड़ी भी हुई है। भले ही इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन उसकी हालत सांप छछूंदर की हो गई है। अराकान आर्मी ने जिस जगह पर अपना ठोस कब्जा कर रखा है बांग्लादेश का यह क्षेत्र गहरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। अराकान आर्मी के पास बांग्लादेशी सेना की तुलना में कहीं बेहतर युद्ध कौशल वाले लड़ाके है। इसलिए, बीजीबी के लिए ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक अराकान का विरोध करना संभव नहीं था। सैन्य विशेषज्ञ कह रहे है कि, चटगांव की ज़मीन खोने के बाद ढाका अब तक इस बारे में अपना मुंह नहीं खोल रहा है। बांग्लादेश की हेकड़ी निकल गई है। यूनुस सरकार अपनी कमज़ोरी छुपा रही है। हालात तो यह है कि बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इस स्थिति पर काबू पाने में नाकाम हो रही हैं। देखा जाए तो अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए भस्मासुर बन गई है। आराकान आर्मी जिसने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वह म्यांमार की सेना से लड़ते भी रही है। इनके पास करीब 30 हजार लड़ाके और उन्नत हथियार है। जानकारों की माने तो अराकान आर्मी बांग्लादेश पर इस तरह से हमले का साहस नहीं कर पता अगर बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बेहद खराब नहीं होते। अराकान आर्मी को पता है कि आज भारत व बांग्लादेश के बीच जिस तरह का तनाव व हालात है उक्त स्थिति में भारत बांग्लादेश की मदद के लिए किसी तरह का सैन्य सहायता नहीं दे सकता है। क्यों कि पिद्दी सा देश बांग्लादेश जिसका जन्म भारत के रहमो करम पर हुआ है। वहीं देश मौलवादी विचार धारा रखने वालों के उकसावे पर भारत से रिश्ते बेहद खराब कर चुका है। इसके साथ ही वह चीन के साजिश में भी फंसता जा रहा है। देखा जाए तो आज बांग्लादेश के प्रमुख कहे जाने वाले यूनुस की आंखों की नींद भी उड़ गई होगी। कुटनीति के जानकारों का मामना है कि फिलहाल बांग्लादेश के जो हालात है और एक तरह से अराकान आर्मी ने इस देश को औकात समझा दी है। इस स्थिति का भारत को फायदा उठाना होगा। अगर भारत इसमे सफल हुआ तो भारत का एहसान फरामोश बांग्लादेश के कई टुकड़े करवाये जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में भारत का डंका बज सकता है और मौलवादी उग्रवादी मानसिकता के लोगों को गहरा धक्का लगेगा।

# शनिदेव को चढ़ाते हैं शमी के पत्ते

## भगवान शिव और गणेश को भी प्रिय है शमी, घर में भी लगा सकते हैं शमी का पौधा

भारतीय संस्कृति में देवी-देवताओं के साथ ही पेड़-पौधों की भी पूजा करने की परंपरा है। पूजनीय पेड़-पौधों में पीपल, आंवला, बरगद, आंकड़ा (मदार), तुलसी, अशोक और शमी का विशेष महत्व है। इनमें शमी के पत्ते के पत्ते बहुत खास हैं, क्योंकि ये पत्ते भगवान शिव, गणेश और शनि देव देव को प्रिय माने गए हैं। शनिवार है और इस दिन शनिदेव को खासतौर पर शमी की पत्ते चढ़ाते हैं।

ज्योतिष की मान्यता है कि हर शनिवार शमी के पत्ते शनिदेव को चढ़ाते हैं तो कुंडली के शनि दोष शांत हो सकते हैं।

**शमी से जुड़ी मान्यताएं**

पौराणिक कथा है कि त्रेतायुग में जब श्रीराम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब श्रीराम ने शमी के पेड़ की पूजा की थी, पूजा के बाद श्रीराम ने रावण का वध किया था।

महाभारत काल में पांडवों को जब अज्ञातवास में जाना था, तब सभी पांडवों ने अपने अस्त्र-शस्त्र शमी के पेड़ में ही छिपाए थे।

वास्तु की मान्यता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से घर के कई वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। शमी की वजह से घर के वातारवण में पवित्रता और सकारात्मक बनी रहती है।

शमी का पूजनीय और पवित्र है। इसकी नियमित रूप से पूजा करने से विचारों में सकारात्मकता बनी रहती है। शिवलिंग पर सौभाग्य पाने की कामना से शमी के पत्ते चढ़ाते हैं। गणेश जी से सुख-समृद्धि पाने की कामना करते हुए शमी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं।

**शनिवार के स्वामी हैं शनिदेव**

शनिदेव शनिवार के स्वामी माने गए हैं। इसी वजह से हर शनिवार शनि देव की विशेष पूजा की जाती है। शनि न्याय के देवता माने गए हैं। ज्योतिष में माना जाता है कि शनि देव ही हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं, शनि की कृपा पाने के लिए तेल का दान, तेल से अभिषेक करने के साथ ही शनि देव को शमी के पत्ते, काले तिल, नीले फूल चढ़ाने की परंपरा है। भगवान को शमी पत्ते चढ़ाते समय ये मंत्र बोलना चाहिए-

**अमंगलानां च शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च।**
**दुःस्वप्रनाशिनीं धन्यां प्रपद्येहं शमीं शुभाम।।**

**घर में किस दिशा में लगा सकते हैं शमी का पौधा**

घर की उत्तर-पूर्व दिशा के कोने में शमी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है।

शनिवार को या किसी अन्य शुभ दिन शमी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। इस पौधे की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए।

भगवान गणेश को हर बुधवार शमी के पत्ते चढ़ाना चाहिए। दूर्वा की तरह ही शमी पत्ते भी गणेश जी को प्रिय हैं। माना जाता है कि शमी में शिव जी का वास है, इसी वजह से ये पत्ते गणेश जी को प्रिय हैं।

आयुर्वेद में शमी के पौधे के कई उपयोग बताए गए हैं। इस पौधे का इस्तेमाल कई औषधियों में किया जाता है।

# भानुमती के एक बेटा और एक बेटी थी

क्या आपने कभी सोचा कि जिस तरह रामायण में रावण की पटरानी यानि मुख्य पत्नी मंदोदरी ने पति की मृत्यु के बाद विश्वासघाती भाई विभीषण से क्यों शादी कर ली थी। ठीक ऐसा ही उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें दुर्योधन की खूबसूरत और चतुर पत्नी भानुमति ने युद्ध में पति के मारे जाने के बाद प्रबल शत्रु रहे पांडव भाइयों में से ही एक से शादी करके घर बसा लिया, फिर जिंदगीभर वह आराम से रही। आखिर किस वजह से भानुमति ने ऐसे काम किए कि एक मुहावरा ही उसके नाम पर पड़ गया।

महाभारत के मुख्य पात्र दुर्योधन के बारे में बहुत लिखा और कहा गया है लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनकी पत्नी कौन थी, जिसे वह बहुत प्यार करते थे। उसका महाभारत के युद्ध में पति समेत कौरवों की मृत्यु के बाद क्या हुआ। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जो अपूर्व सुंदरी थी।

आंचलिक कथाओं में ये कहा गया कि जब दुर्योधन नहीं रहा तो भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि दुर्योधन से विवाह करने से पहले वह मन ही मन अर्जुन को चाहती थीं। हालांकि अर्जुन से विवाह के कोई पुख्ता साक्ष्य महाभारत या उसकी उत्तर कथा वाले ग्रंथों में नहीं मिलते।

महाभारत के मुताबिक दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। महाभारत में दुर्योधन की पत्नी का तीन बार ज़िक्र मिलता है। शांति पर्व में बताया गया है कि दुर्योधन ने कर्ण की मदद से राजा चित्रांगद की बेटी भानुमति का स्वयंवर से अपहरण करके विवाह कर लिया था।

बाद में, स्त्री पर्व में भी दुर्योधन की मां गांधारी ने भानुमति का ज़िक्र किया है। भानुमती के एक बेटा और एक बेटी थी।

शांति पर्व में ऋषि नारद दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में एक कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि किस तरह कर्ण की मदद से दुर्योधन ने कलिंग राजा चित्रांगद की बेटी का अपहरण कर शादी की थी।

भानुमति के बारे में उल्लेख किया गया है कि वह ताजिंदगी कृष्ण की पूजा करती रही। बेशक उसके पति दुर्योधन ने कई बार कृष्ण को खरीखोटी सुनाई, अपमान भी किया लेकिन भानुमति के लिए वह हमेशा आराध्य रहे। यहां तक कि पति के निधन के बाद भी वह उनकी भक्त बनी रही। महाभारत के स्त्री पर्व में दुर्योधन की मां गांधारी , कृष्ण से अपनी पुत्रवधू का वर्णन इस प्रकार करती हैं। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद महाभारत के युद्ध में मारा गया। बेटी का नाम लक्ष्मणा था।

गांधारी कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण! देखो, ये दृश्य मेरे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुःखदायी है। दुर्योधन की प्रिय पत्नी महाबुद्धिमान कन्या है, देखो वह कैसे अपने पति और बेटे के लिए विलाप कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भानुमति ने पति दुर्योधन के सबसे बड़े दुश्मन पांडु पुत्र अर्जुन से क्यों विवाह कर लिया। भानुमति जितनी रूपवती थी, उतनी ही चतुर भी। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, तब भानुमति को पता था कि कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। अपने कुनबे को बचाने के लिए उसने ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भगाकर ले जाने की युक्ति सुझाई।

एक अन्य कथा के अनुसार साम्ब जब लक्ष्मणा का अपहरण कर फरार हो गया तो भानुमति ने दुर्योधन को अपने अपहरण की याद दिलाई और साम्ब से लक्ष्मणा के विवाह में अहम भूमिका निभाई। भानुमति ने अपने कुनबे को बचाने के लिए हर वो असंगत कार्य किया, हर उस चीज को जोड़ा, जिसका जुड़ना संभव नहीं था। इसीलिए कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, संबंधित कहावत बनी।

**-समाप्त**

मुश्किल समय में मित्र, युद्ध में वीर,
एकांत में पवित्रता की परख होती है।
मुश्किल समय में अच्छे मित्र साथ देते हैं।
युद्ध में वही जीतता है जो वीर है। एकांत में
जो व्यक्ति तन, मन और कर्म से पवित्र
रहता है, वही श्रेष्ठ इंसान होता है।

गरुड़ पुराण, नीतिसार

# इंटरव्यू में पाना है सफलता तो पॉकेट में डालें 1 खास चीज

वास्तु शास्त्र में कई नियम और उपाय बताए जाते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में घटने वाली कई चीजों को पॉजिटिव कर सकते हैं। जिस तरह वास्तु शास्त्र में घर और घर में रखे सामान के लिए वास्तु टिप्स होते हैं उसी प्रकार इंटरव्यू में सफलता प्राप्त हो इसके लिए भी वास्तु के कुछ उपाय बताए जाते हैं। जी हां, कई बार अनेकों प्रयासों और अच्छे क्वालिफिकेशन के बाद भी लोगों को मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है। जिससे की लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र में इंटरव्यू पर जाने से पहले के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें कर लेने से इंटरव्यू में पॉजिटिव परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से किन उपायों को करना शुभ रहेगा।

**करें गणेश जी की आराधना**

हिंदू धर्म के अनुसार गणेश जी की आराधना हर शुभ काम से पहले की जाती है। इसी तरह वास्तु के अनुसार अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पहले गणेश जी का आराधना करें और उन्हें सुपारी और प्रसाद के रुप में मोदक का भोग लगाकर घर से जाएं। यह उपाय बहुत कारगार माना जाता है।

**घर से निकलते समय रखें ये पैर**

जब आप इंटरव्यू के लिए घर से निकल रहे हैं तो ऐसे में पहले अपना दायां पैर आगे रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपके इंटरव्यू में सफलता मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।

**अपनी पॉकेट में डाल लें ये चीज**

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऐसे में आप पहले अपनी पॉकेट में पीले रंग का कोई रुमाल या फिर पीले रंग का कोई छोटा सा कपड़ा डाल लें। ऐसा करने से आपको इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

**पर्स में रखें ये चीजें**

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो जाने से पहले या तो पर्स में चावल के कुछ दाने डाल लें या फिर गोमती चक्र डाल लें। ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

# सांप काटे व्यक्ति को जिंदा कर देता है यह मंदिर

## चमत्कारिक है बैदेही बाबा की कथा!

जिले के महाराजपुर गांव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर बिदेही बाबा जहां सर्पदंश के मरीज ठीक होते हैं। मान्यता है कि इस मेले पर जो भी व्यक्ति पहुंचता है उसे सबसे पहले मंदिर पर नारियल पान बताशा चढ़ाना होता है। इसके बाद ही वह मेला घूमता है और सामान खरीदकर घर जाता है।

यह स्थान राजाओं के जमाने का है। एक राजा ही यहां आए थे और एकांत इस जंगल में रहने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने जिंदा समाधि ले ली। आज मंदिर भी इसी समाधि के ऊपर बना है। यहां जो भी सर्पदंश का मरीज आता है, ठीक होकर ही जाता है।आज भी उनका आशीर्वाद यहां आने वाले लोगों को मिलता है। बता दें, इस स्थान पर एक नाग देवता भी रहते हैं जिसकी पुजारी ही देखभाल करते हैं।

**100 साल से भी पुराना है मेला**

पुजारी बताते हैं कि यहां 100 साल से मेला लग रहा है। ये मेला पुरखों से लगता आ रहा है। हर दिन इस मेले में हजारों-लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस स्थान की मान्यता मान्यता है कि यहां की धरती पर जो भी पग रखता है उसे सबसे पहले बिदेही बाबा महाराज के यहां परिक्रमा लगाना होता है। इसके बाद नारियल पान बताशा चढ़ने की परंपरा है। फिर यहां मेला घूमने की मान्यता है। मेला देखने से ज्यादा लोग यहां बिदेही बाबा महाराज के दर्शन करने आते हैं। इस मेले सिर्फ एमपी से ही नहीं बल्कि यूपी से भी लोग आते हैं।

**सांप काटे टे तो ऐसे होता है उपचार**

पुजारी राजकुमार तिवारी के मुताबिक यदि किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले बैदेह बाबा की जय बोलकर बालों में गांठ लगा ले, इसके बाद घी-कालीमिर्च पी ले लेकिन पानी नहीं पीना हैं। इसके तुरंत बाद बैदेही बाबा मंदिर आना हैं और बाबा की जय बोलकर परिक्रमा लगाना हैं। कितना भी जहरीले सांप ने काटा हो बाबा उसे बचा लेंगे।

**यहां आने के बाद कोई भी सर्पदंश का व्यक्ति नहीं मरा**

पुजारी राजकुमार के मुताबिक यदि जिंदा हालत में यहां कोई सांप का मरीज आया है तो फिर यहां से जीवित ही गया है। हर दिन सर्पदंश के 20-25 मरीज़ आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। कई बार तो रात में भी आते हैं फिर हम भी घर से भागकर मंदिर आते हैं और परिक्रमा लगवाकर उपचार करवाते हैं।

# नए साल में शनि होंगे वक्री

## 138 दिन चमकेगी इन राशियों की किस्मत

**मकर राशि**

नए साल 2025 में मकर राशि के जातकों के लिए शनि की वक्री चाल आर्थिक उन्नति के संकेत दे रही है। करियर में प्रमोशन या व्यापार में बड़ा मुनाफा हो सकता है। घर की आमदनी में इजाफा होगा। रुके हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं। निवेश के लिए यह समय शुभ साबित होगा। समाज में आपको भरपूर मान-सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

**कुंभ राशि**

शनि की उल्टी चाल कुंभ राशि वालों को सफलता के नए अवसर प्रदान कर सकती है। इन दिनों नौकरीपेशा लोग वेतन वृद्धि की उम्मीद रख सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। भाग्य आपके साथ रहेगा और धन के योग बनेंगे। इस दौरान आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इन दिनों आपकी सोची हुई योजनाएं सफल हो सकती हैं। घर वालों के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। इसके अलावा व्यापार-करोबार, वाणी और मीडिया से जुडें हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है।

**मिथुन राशि**

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की वक्री चाल की अवधि विशेष लाभकारी साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और नई संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। निवेश और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उनकी ये तलाश पूरी हो सकती है। आपको कारोबार या बिजनेस के ऑफर मिल सकते हैं, जो लाभकारी सबित हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत रहेंगे।

**इन बातों का रखें ध्यान**

शनि की वक्री चाल के दौरान लाभ पाने के लिए भगवान शनि की पूजा और दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसे में जरूरतमंदों को काला तिल, काले कपड़े और सरसों का तेल दान कर सकते हैं।

# शनिदेव को क्यों कहा जाता है न्याय का देवता, किसने दिया था वरदान

शनिदेव भगवान को न्याय का देवता कहा जाता है। क्योंकि वह मनुष्यों को उनके कर्मों के आधार पर न्याय देते हैं। शनिदेव को उनके न्यायप्रिय स्वभाव के कारण न्यायाधीश और कर्मफलदाता के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करके उनकी तीव्र दृष्टि से बच नहीं सकता। वह मनुष्य को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार तुरंत फल देते हैं।

**क्यों कहा जाता है न्याय के देवता**

भगावन शनिदेव का संबंध न्याय और कर्मफल से जोड़ा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उचित दंड या शुभ फल प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब किसी मनुष्य के जीवन में बुरा समय चल रहा होता है, तो कहा जाता है कि शनिदेव उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। जो व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा दे रहे होते हैं।

**शनिदेव रखते हैं कर्मों का लेखा-जोखा**

इसके साथ ही शनि की साढ़े साती और ढैया जैसे समय-चक्र के माध्यम से शनिदेव अपने उपासकों को उनके जीवन के कर्मों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं। यह समय गलत कर्म करने वाले जातकों के लिए कठिन हो सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और साथ ही भगवान शनिदेव की पूजा करता है, तो उसे शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनको भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है साथ ही जीवन आनंदमय गुजरता है।

**किसने दिया शनि देव को वरदान**

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। जिसमें उन्होंने शनिदेव को मनुष्यों के कर्मों के अनुसार न्याय और फल देने का वचन दिया था । एक अन्य कथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। उन्होंने कठोर तपस्या करके यह शक्ति प्राप्त की कि वे संसार के हर प्राणी को न्याय दिलाएंगे। इसके अलावा शनिदेव को उनकी न्यायप्रियता के लिए मृत्यु के देवता यमराज से भी सम्मान मिला था। यही वजह है कि शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मों का फल देने वाला माना जाता है।

# क्या महाकुंभ में नागा साध्वी भी करती हैं शाही स्नान

**नागा साध्वी करती हैं पवित्र शाही स्नान**

महिला नागा साधुओं को नागा साध्वी भी कहा जाता है। महिला नागा साध्वी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही कठिन तपस्या और दीक्षा के बाद नागा संप्रदाय में शामिल होती हैं। महाकुंभ के दौरान महिला नागा साध्वी भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही अखाड़ों के साथ पवित्र स्नान करती हैं। गुरुओं की आज्ञा के अनुसार वे भी अपनी आस्था और परंपरा का ध्यान रखते हुए नग्न अवस्था में स्नान करती हैं और पूरे अनुशासन तथा मर्यादा का पालन करती हैं।

**महिला नागा साध्वियों के शाही स्नान का महत्व**

महाकुंभ के दौरान नागा साध्वियों के शाही स्नान का महत्व विशेष महत्व है। इसे पवित्रता, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम माना गया है। इसमें महिला नागा साध्वियां प्रमुख अखाड़ों के झंडे और हथियारों तलवार, त्रिशूल, चिमटा के साथ भव्य शोभायात्रा निकालती हैं। इसके बाद स्नान करती हैं। यह दृश्य न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह महिलाओं की आध्यात्मिक ताकत और उनके समर्पण को भी दर्शाता है।

**महिला नागा साध्वियों का समाज को संदेश**

महाकुंभ में महिला नागा साधुओं की उपस्थिति समाज को एक बड़ा संदेश देती है। इससे यह साफ होता है कि महिलाएं अध्यात्म और साधना में पुरुषों से पीछे नहीं हैं और दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। इन साध्वियों का शाही स्नान भारतीय संस्कृति में महिलाओं के समान अधिकार और सम्मान को दर्शाता है। इसके साथ ही यह नारी शक्ति के आत्मबल को प्रगाढ़ करता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

## कुवैत की दो दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी

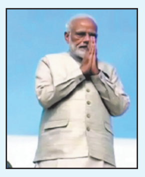

**नईदिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुवैत की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले शनिवार को कहा कि पश्चिम एशियाई क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भारत और खाड़ी देश का साझा हित है। मोदी ऐसे समय में कुवैत की यात्रा कर रहे हैं जब दो सप्ताह पहले सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन का पतन हो गया और गाजा में इजराइल के हमले जारी हैं। पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले दिए गए एक बयान में कहा कि कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत भारत और कुवैत के बीच भविष्य की साझेदारी का खाका तैयार करने का अवसर देगी। उन्होंने कहा, ''हम कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं, जो पीढ़ियों से कायम हैं। हम न केवल व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्रों में मजबूत साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भी हमारा साझा हित है।'' मोदी ने कहा कि वह कुवैत के अमीर, युवराज (क्राउन प्रिंस) और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठकों के लिए उत्सुक हैं।

## कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत जाने पर कसा तंज

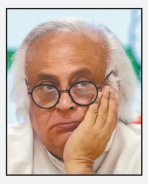

**नई दिल्ली।** कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी कुवैत यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा। सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि लगातार यात्रा करने वाले पीएम कुवैत चले गए हैं, जबकि हिंसा प्रभावित मणिपुर के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक तंज कसते हुए पोस्ट किया। उन्होंने कहा, ऐसा है उनका हाल, जैसे मोदी को नहीं मिल रही कोई तारीख, मणिपुर के लोग इंतजार कर रहे, जबकि लगातार यात्रा करने वाले पीएम कुवैत जा रहे हैं। कांग्रेस ने बार-बार प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर जाने की मांग की है, उनका कहना है कि यह राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करेगा। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कुवैत की दो दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों में इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है।

## एलजी ने दी केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी

**नईदिल्ली।** राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय को उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी क्योंकि उसे कथित तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के तैयार करने और कार्यान्वयन में भारी स्तर पर भ्रष्टाचार मिला था, जिसका उल्लेख अभियोजन शिकायत संख्या में किया गया था। ईडी ने इसी साल 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया था। कोर्ट ने 9 जुलाई को शिकायत पर संज्ञान लिया। आप ने कहा कि तथाकथित शराब घोटाले की जांच दो साल तक चली, 500 लोगों को परेशान किया गया, 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए गए और 250 से अधिक छापे मारे गए, एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ। और मामले में कई छेद किए गए हैं।

## भाजपा प्रताप सारंगी के गाल की हड्डी पर सूजन

**नई दिल्ली।** राम मनोहर लोहिया ने शनिवार को भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के स्वास्थ्य पर अपडेट दिया। आरएमएल के एमएस डॉ. अजय शुक्ला ने बताया कि सारंगी के गाल की हड्डी पर सूजन और नीलापन है। जांच के लिए एक्स-रे की योजना बनाई गई है। डॉक्टर ने कहा कि भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। उन्हें बेचैनी हो रही है। घायल भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर आरएमएल एमएस डॉ. अजय शुक्ला ने कहा, आज हमने देखा कि सारंगी कि उनके गाल की हड्डी पर सूजन और नीलापन है। हम एक्स-रे करवाने जा रहे हैं कि क्या यह कोई मामूली फ्रैक्चर है या भौं के ऊपर चोट की वजह से है और खून नीचे की ओर बह रहा है। गाल की हड्डी पर थोड़ा खून जमा हुआ है। मुकेश राजपूत को अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है।

## जॉर्ज सोरोस को लेकर भिड़े हरदीप पुरी और शशि थरूर

**नई दिल्ली।** भारतीय राजनीति में इन दिनों अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की चर्चा गर्म है। भाजपा, कांग्रेस नेतृत्व के जॉर्ज सोरोस के साथ कथित संबंधों को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। अब सोरोस को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी सोशल मीडिया पर भिड़ गए हैं। थरूर ने कहा कि विदेश राज्यमंत्री के तौर पर मैं न्यूयॉर्क के दौरे पर था। उस वक्त अमेरिका में भारत के राजदूत हरदीप पुरी ने कई प्रमुख अमेरिकियों को मेरे साथ डिनर पर चर्चा के लिए बुलाया था। थरूर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लोग 15 साल पुराने ट्वीट के आधार पर बेतुका आरोप लगा रहे हैं। शशि थरूर के आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शशि थरूर ने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई है। पुरी ने बताया कि साल 2009 के जिस डिनर की बात थरूर कर रहे हैं, उसमें आमंत्रित लोगों की सूची उन्होंने ही दी थी और जिन सज्जन की बात की जा रही है, वो राजीव गांधी फाउंडेशन के दानदाता थे और तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री ही उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे।

# रूस के कजान में 9/11 जैसा हमला

## किलर ड्रोन से यूक्रेन ने किया अटैक, कई इमारतों से टकराए ड्रोन

**कजान।** रूस के कजान शहर में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। रूसी मीडिया के अनुसार, कजान में कई बहुमंजिला इमारतों से ड्रोन्स टकराए हैं। यह हमला अमेरिका में साल 2001 में हुए 11 सितंबर जैसे हमले की तरह किया गया है। इस हमले में हुए नुकसान की अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ड्रोन्स रिहायशी इमारतों से टकराए हैं और इमारतों में धमाके हुए और आग लगी, उससे बड़े नुकसान की आशंका है। हमले के वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं रूस के कुर्स्क क्षेत्र में रिलस्क शहर में यूक्रेन के मिसाइल हमले में एक बच्चे समेत छह लोगों की मौत की खबर है। हमले में 10 अन्य लोग घायल भी हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये हमले यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। ड्रोन्स हमलों के बाद कजान एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कजान की छह रिहायशी इमारतों पर ये ड्रोन हमले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कजान शहर यूक्रेन की सीमा से करीब 900 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और पूर्व में भी यूक्रेन की तरफ से कजान में ड्रोन हमले किए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उनके बलों ने 12 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया है। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि बीती रात रूस के रोस्तोव में भी दो तेल डिपो में आग लगने की घटना हुई। यह आग भी कथित यूक्रेनी ड्रोन हमले के चलते लगी।

बीते अक्तूबर में ही कजान शहर ब्रिक्स सम्मेलन के चलते दुनिया भर में चर्चा में रहा था। रूस ने कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। कजान का रूस के इतिहास में अहम स्थान है और ये शहर रूस के उद्योग, संस्कृति और धर्म का प्रमुख केंद्र है। इसे रूस की तीसरी राजधानी या खेल राजधानी भी कहा जाता है। रूस, कजान में कई अंतरराष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों की मेजबानी कर चुका है। आर्थिक रूप से कजान एक पावरहाउस है। यह शहर रूस के प्रमुख ट्रक निर्माता कामाज का घर है और यात्री हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कजान के इंजीनियरिंग, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काफी समृद्ध हैं।

### महा विकास अघाड़ी में आई दरार!

## पार्टी अकेले लड़ सकती है बीएमसी चुनाव: राउत

**मुंबई।** महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। इस बीच, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव में अकेले उतर सकती है, हालांकि वे महा विकास आघाड़ी (एमवीए) का साथ नहीं छोड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या लोकसभा और विधानसभा चुनावों से ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा, उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं के बीच इस बारे में बातचीत चल रही है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ें।

शिवसेना ने 1997 से 2022 तक लगातार बीएमसी पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। पिछला मुंबई नगर निगम चुनाव मार्च 2022 में समाप्त हुआ था और अब तक नए चुनाव नहीं हुए हैं।

राउत ने कहा कि मुंबई में शिवसेना की शक्ति अप्रतिबंधित है और अगर उन्हें विधानसभा चुनावों में अधिक सीटें मिलतीं तो वे जीत सकते थे। उन्होंने कहा कि जब अविभाजित शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन में थी, तब भी वे बीएमसी और अन्य स्थानीय चुनावों में अकेले चुनाव लड़ते थे और अब भी इसी तरह से चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है।

पिछले सप्ताह, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि शिवसेना बीएमसी चुनाव महायुति (गठबंधन) के तहत लड़ेगी, जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं।

# प्रियंका के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती

**नईदिल्ली।** कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, अब प्रियंका गांधी की सांसदी पर तलवार लटक रही है। असल में भारतीय जनता पार्टी की नेता नव्या हरिदास ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रियंका गांधी के वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती दी है।

भाजपा नेता नव्या हरिदास ने 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी की हालिया चुनावी जीत को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट दरवाजा खटखटाया है। हरिदास भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में खड़ी हुई थीं, लेकिन प्रियंका गांधी से 5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई थीं। नव्या हरिदास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्यन मोकेरी से भी काफी पीछे तीसरे स्थान पर थीं।

भाजपा नेता नव्या हरिदास शुक्रवार 20 दिसंबर 2024 को केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में हरिदास ने तर्क दिया है कि प्रियंका गांधी ने अपने नामांकन पत्र में अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का सही खुलासा नहीं किया है और इससे जुड़ी कई अहम जानकारी छिपाई गई है। भाजपा नेता हरिदास के मुताबिक प्रियंका गांधी ने मतदाताओं को गुमराह किया, गलत सूचना दी और मतदाताओं को अंधेरे में रखा, ताकि मतदाताओं की पसंद को प्रभावित किया जा सके। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रियंका गांधी ने कई मौकों पर मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाला और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण में लिप्त रही हैं। भाजपा नेता हरिदास ने भी तर्क दिया है कि प्रियंका गांधी का नामांकन पत्र चुनाव कानूनों और चुनाव संचालन नियमों के तहत जनादेश का उल्लंघन करता है। इन आधारों के अलावा, भाजपा नेता हरिदास ने प्रियंका गांधी की चुनावी जीत को खारिज करने की मांग की है। हरिदास की ओर से अधिवक्ता हरि कुमार जी नायर पेश होंगे। प्रियंका गांधी का वकील कौन होगा इसपर अभी कोई अधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है। प्रियंका गांधी से जुड़े इस मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में होने की संभावना है...क्योंकि हाई कोर्ट में 23 दिसंबर से पांच जनवरी तक अवकाश रहेगा। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या भाजपा नेता के इस कदम के बाद प्रियंका गांधी की सांसदी छिन जाएगी? फिलहाल इस बात का फैसला तो कोर्ट तय करेगी।

# आंबेडकर मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ खुलकर उतरे माया-ममता

## बसपा का 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन, टीएमसी 23 को करेगी राज्यव्यापी प्रदर्शन

**नईदिल्ली।** मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ 23 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और पार्टी पर संविधान निर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए कड़े शब्दों वाले बयान में बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंबेडकर और संविधान मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।

बंगाल सीएम ने कहा कि हमारे संविधान निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर का अपमान अस्वीकार्य है! इस जातिवादी भाजपा सरकार ने हमारे लोकतंत्र पर बार-बार हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की हरकतें

उसके दलित विरोधी एजेंडे को उजागर कर रही हैं। टिप्पणी को संविधान की रीढ़ पर हमला बताते हुए बनर्जी ने पूरे बंगाल में लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान के विरोध में 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक राज्य के हर ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता के हर वार्ड में विरोध रैलियां आयोजित की जाएंगी।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर संसद में जो बयान दिया है उससे सर्वसमाज के लोग काफी उद्वेलित और आक्रोशित हैं और पार्टी शाह के बयान के विरोध में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगी। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्म-सम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति-मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर भगवान की तरह परमपूजनीय हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

## पिछले 10 वर्षों में एमसीजी पर एक भी टेस्ट नहीं हारा भारत

**मेलबर्न।** भारतीय टीम पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को पीछे छोड़त हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 1-1 की बराबरी पर चल रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिसबेन के गाबा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था और अब रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम की नजरें 26 दिसंबर से होने वाले चौथे टेस्ट के दौरान मेलबर्न पर जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल करने पर टिकी होंगी।

भारत को अगर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में जगह बनानी है तो उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले दोनों मुकाबले जीतने होंगे। इस सीरीज में एक और हार उसके लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल के दरवाजे बंद कर देगी। भारत ने विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कराया उससे टीम के हौसले बढ़े हुए होंगे। भारत अगर चौथा मैच जीतने में सफल रही तो सीरीज गंवाने से बच जाएगी और 2-1 की बढ़त हासिल कर लेगी।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी है। पिछले 10 वर्षों में टेस्ट में यह ग्राउंड भारत के लिए अजेय किला बना हुआ है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर 2014 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल तीन मुकाबले खेले हैं और उसे दो में जीत मिली है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है। वहीं, पैट कमिंस की अगुआई वाली टीम पिछले 10 वर्षों में एमसीजी पर भारत के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर सकी है। यह आंकड़े भारत के लिए राहत देने वाले हैं क्योंकि टीम की नजरें बढ़त हासिल करने पर टिकी हुई हैं। पिछले 10 वर्षों में भले ही एमसीजी में भारत ने सफलताएं हासिल की है, लेकिन ओवरऑल इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का ही दबदबा रहा है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

## वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक शुरू

**नई दिल्ली।** जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य, जीवन बीमा पॉलिसियों पर कर कटौती के निर्णय को स्थगित करने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के बीच अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशों में 148 वस्तुओं की दरों में बदलाव का प्रस्ताव किया था। लेकिन सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि पैनल की ओर से सुझाए गए कुछ कर परिवर्तनों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है और इसके लिए कुछ और समय की जरूरत हो सकती है। स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर जीएसटी दर को वर्तमान 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

## मुद्रास्फीति-वृद्धि का संतुलन बहाल करना हो प्राथमिकता

**मुंबई।** मौद्रिक नीति की प्राथमिकता मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन को बहाल करने की होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर शक्तिकान्त दास ने इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में यह बात कही थी। ब्याज दर निर्धारण करने वाली एमपीसी में दास के अलावा तीन अन्य सदस्यों ने भी रेपो दर को 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने के पक्ष में मतदान किया था। दूसरी ओर शेष दो सदस्यों ने दर में कटौती का पक्ष लिया था। आरबीआई ने शुक्रवार को दिसंबर की शुरुआत में हुई एमपीसी बैठक का ब्योरा जारी किया। इस ब्योरे के मुताबिक, दास ने बैठक में कहा, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर नीतिगत प्राथमिकता मुद्रास्फीति-वृद्धि के संतुलन को बहाल करने पर होनी चाहिए। अब बुनियादी जरूरत मुद्रास्फीति को कम करने की है।

## बिजली वितरण कंपनियां राज्यों पर वित्तीय रूप से बोझ बनीं

**नई दिल्ली।** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) राज्यों के लिए वित्तीय रूप से भारी बोझ बनी हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य डिस्कॉम का कुल संचित घाटा 2022-23 तक 6.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियाँ राज्यों पर वित्तीय रूप से बोझ बनी हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न सुधार प्रयासों के बावजूद डिस्कॉम राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। हालात बदलने के लिए, आरबीआई ने उत्पादकता में सुधार, ट्रांसमिशन और वितरण घाटे को कम करने और बिजली आपूर्ति की वास्तविक लागत के साथ टैरिफ को एडजस्ट करने जैसे उपायों के महत्व पर जोर दिया। आरबीआई की रिपोर्ट में पाया गया है कि राज्यों ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने में प्रगति की है।

## आर्थिक मंदी पर तत्काल नीतिगत ध्यान देने की जरूरत

**नई दिल्ली।** भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य नागेश कुमार के अनुसार देश में चल रही आर्थिक मंदी इस हद तक गंभीर हो गई है, जिसपर तत्काल नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। दिसंबर एमपीसी बैठक के दौरान रेपो दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की वकालत करते हुए , कुमार ने घटती वृद्धि और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं की दोहरी चुनौतियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी बैठक के मिनटों के अनुसार, इसके सदस्य नागेश कुमार ने जोर देकर कहा कि अक्तूबर 2024 की एमपीसी बैठक के बाद से आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। कुमार ने भारत की आर्थिक वृद्धि में भारी गिरावट की ओर इशारा किया।

# आरबीआई की नीतियां: फूंक-फूंक कर कदम रख रहा केंद्रीय बैंक

**अजय बग्गा**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार ग्यारहवीं बार रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा जाना, धीमी होती आर्थिक वृद्धि और लगातार मुद्रास्फीति के दबाव के बीच सतर्कता का संकेत है। रेपो दर को 6.5 फीसदी बनाए रखने का फैसला रिजर्व बैंक के विकास को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दोहरे उद्देश्य को रेखांकित करता है। अक्तूबर में मुद्रास्फीति की दर 6.2 फीसदी थी, जो छह फीसदी की ऊपरी सहनीय सीमा से अधिक थी।

रिजर्व बैंक व्यापक रूप से उधार लेने की लागत को कम करने में हिचकिचा रहा है। दरों को स्थिर रखने के निर्णय के बावजूद रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की कटौती की है। इसे 4.5 फीसदी से घटाकर चार फीसदी करने के निर्णय से बैंकिंग प्रणाली में 1.16 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता आएगी और बैंकों की सकल आय में प्रति वर्ष लगभग 8,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। रिजर्व बैंक का नजरिया संतुलन दर्शाता है।

रिजर्व बैंक आर्थिक मंदी के जोखिमों से निपटते हुए मुद्रास्फीति को दो से छह फीसदी के भीतर रखने को प्राथमिकता में रख रहा है। यह फैसला वैश्विक मौद्रिक रुझानों के अनुरूप है, जहां विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक अस्थिर वैश्विक स्थितियों और अगले वर्ष राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाइयों के कथित जोखिमों के प्रति सतर्क हो रहे हैं। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह दर में कटौती के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करने का एक खोया हुआ अवसर हो सकता है,

क्योंकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 की तीसरी तिमाही में 5.4 फीसदी है, जो सात तिमाहियों का निचला स्तर है। एक लोकप्रिय वित्तीय एजेंसी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 50 में से मात्र सात अर्थशास्त्रियों ने इस बार दरों में कटौती की घोषणा की थी। यह देखते हुए रिजर्व बैंक के पास मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए गुंजाइश है, जैसा कि इसके घोषित जनादेश में कहा गया है, और लगातार दो महीनों से उपभोक्ता मुद्रास्फीति छह फीसदी की सीमाओं के पार है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रिजर्व बैंक इस बार दरों में कटौती नहीं करेगा।

इसके अलावा, डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने डॉलर के मजबूत होने, वैश्विक मुद्राओं के कमजोर होने, अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स की पैदावार में उच्च वृद्धि के लिए मंच तैयार किया है। कर कटौती, कम विनियमन, उच्च टैरिफ और समग्र संरक्षणवाद की ट्रंप की अपेक्षित नीति के कारण उभरते बाजारों से धन का प्रवाह अमेरिकी बाजारों में हो रहा है। आरबीआई के सामने यह मुश्किल चुनौती थी कि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करे और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दे, जो स्पष्ट रूप से धीमी पड़ रही है और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि भारतीय रुपये पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। भारतीय रुपये में व्यवस्थित अवमूल्यन आरबीआई का अघोषित लक्ष्य है।

लोकसभा चुनाव के कारण, मार्च से जून की अवधि में केंद्र सरकार के बुनियादी ढांचे के खर्च और नई परियोजनाओं को मंजूरी देने में कटौती की गई थी। जुलाई 2024 में केंद्रीय बजट पारित होने के बाद भी केंद्र सरकार का खर्च कम रहा है और बजटीय अनुमान से नीचे रहा है। केंद्रीय खर्च में यह धीमी वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, कोई कर रियायत नहीं और डेढ़ साल से अधिक समय तक उच्च ब्याज दरें जारी रहने से निजी खपत में गिरावट आई है। उपभोक्ता मांग में इस गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के परिणामों में कॉरपोरेट आय में धीमी वृद्धि हुई। ऐसे में समय की मांग थी कि राजकोषीय और मौद्रिक, दोनों मोर्चों पर प्रति-चक्रीय (काउंटर-साइक्लिक) प्रोत्साहन दिया जाए। पीछे मुड़कर देखने पर रिजर्व बैंक की ब्याज दरों को स्थिर रखने की नीतिगत कार्रवाई एक छूटा हुआ अवसर हो सकती है।

**मुख्यमंत्री आयोजित राज्य स्तरीय पंथी नृत्य एवं गुरू घासीदास लोककला महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल**

# छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के विचारों की छाया-साय

**रायपुर।** मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय बेमेतरा जिले के विकासखंड मुख्यालय नवागढ़ में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता एवं गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नवागढ़ में बाबा गुरु घासीदास जैतखम में पूजा-अर्चना कर राज्य की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर 209 करोड़ 12 लाख 57 हजार रूपये के 74 विभिन्न विकास कार्यो का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने नवागढ़ के कोदूराम दलित महाविद्यालय में एमकाम और साइंस विषय की 40-40 सीट और अनुसूचित जाति बाहुल्य 10 ग्रामों में 10-10 लाख रूपये की सीसी रोड का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का समाज एक समतामूलक समाज है। इस समाज के निर्माण में बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों की छाया स्पष्ट नजर आती है। मनखे-मनखे एक समान के अपने संदेश से यही बात उन्होंने कह दी। जब एक दूसरे को समानता के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे तो बैरभाव स्वत: ही समाप्त हो जाएगा। उनका यह संदेश केवल समाज ही नहीं अपितु देश-दुनिया को एकजुटता के सूत्र में बांधता है। ऐसे समय में जब विघटनकारी तत्व देश की एकता को तोड़ने की साजिश में लगे हैं, बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश प्रकाश स्तंभ की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान के कटोरे की पहचान जिन किसान भाइयों से है, वे सुखी समृद्ध रहें इसके लिए हम किसान भाइयों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। पिछली बार हमने 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, इस बार उम्मीद है कि धान खरीदी का यह आंकड़ा 160 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। बाबा जी ने महिला और पुरुषों के बीच समानता का संदेश भी दिया है। यह समानता तब आयेगी जब आर्थिक रूप से भी हमारी माताएं-बहनें पूरी तरह से सशक्त हों, इसके लिए ही मोदी जी ने हमारी माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना के रूप में हर महीने एक हजार रुपए की गारंटी दी। शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही हमने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए काम करना आरंभ कर दिया था। तीन महीने के भीतर ही हमने 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में हर महीने एक हजार रुपए की राशि देनी आरंभ कर दी। अब तक हम योजना की दस किश्त दे चुके हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सकें, परीक्षाओं में पूरी तरह पारदर्शिता हो, इसके लिए भी हमने कार्य किया। पीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस साल पीएससी की परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हुई। मैं पीएससी के टापर्स से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि पिछली सरकार में जमकर हुए भ्रष्टाचार के चलते बहुत से युवाओं का पीएससी से भरोसा उठ गया था।

# बुनकर संघ के लिए मूणत देंगे 25 लाख

## त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह की 133 वीं जयंती मनाई गई

**रायपुर।** स्वाधीनता संग्राम सेनानी, रायपुर के प्रथम विधायक, नेता प्रतिपक्ष नागपुर असेंबली, रायपुर नगर पालिका के तीन बार अध्यक्ष रहे तथा सहकारिता के अग्रदूत त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह की 133 वीं जयंती आज नगर निगम के जोन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह का संपूर्ण जीवन देश और समाज के लिए त्याग और तपस्या का रहा है। उन्होंने न केवल स्वाधीनता संग्राम में अग्रणीय भूमिका निभाई, बल्कि किसानों, मजदूरों, छात्रों को संगठित कर उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ी थी।

ठाकुर साहब को पद की लालसा कभी नहीं रही, जब उनकी आवश्यकता संत विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में हुई तब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों को छोड़ भूदान यज्ञ में गरीब नारायणों को प्राथमिकता दी थी। 1920 में राजनांदगांव के बीएनसी मिल्स में श्रमिकों को संगठित कर उनके अधिकारों के लिए 33 दिनों की सफल हड़ताल की थी। वह छत्तीसगढ़ की पहली श्रमिक हड़ताल थी। श्री देव ने कहा कि ठाकुर साहब का संपूर्ण जीवन प्रेरक रहा है। उनकी जीवनी और अन्य सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए ताकि आज के बच्चे और युवा उनसे प्रेरणा ले सकें। जयंती समारोह में उपस्थित रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने कहा कि एक दिन प्रतिमा पर फूल माला अर्पित करने के साथ ही स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को हमेशा किस तरह से स्मरण किया जाए आज आवश्यकता इस बात की है। उन्होंने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह के कार्यों से हमें सीखने की और अपने चरित्र में उसे उतारने की भी जरूरत है।

# आत्मविश्वास और उत्साह से मेहनत करने में मिलती है सफलता : साव

**रायपुर।** अपनी मंजिल तय करते वक्त खुद को किसी सीमा में न बांधें, आत्मविश्वास के साथ शत प्रतिशत मेहनत करें। जो युवा आत्मविश्वास और उत्साह से भरा होता है वही सफल होता है और इतिहास बनाता है। असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्न करने से सफलता अवश्य मिलती है। उक्त बातें उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने डागा कन्या महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में कही।

उप मुख्यमंत्री श्री साव आज राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए वार्षिक उत्सव का अलग महत्व होता है। कार्यक्रम के आयोजन से विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर मिलता है एवं उनमें आत्म विश्वास की वृद्धि होती है।

इस दौरान कार्यकम की अध्यक्षता राष्ट्रीय विद्यालय समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिवारी ने की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. संगीता घई के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिये छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम में उपाध्यक्ष श्री गोवर्धन दास डागा मदन लाल तालेडा, सचिव श्री अनिल कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री राज किशोर नत्थानी, श्री देवीचंद श्रीमाल, श्री रूपचंद श्रीमाल, श्री सुरेश शुक्ला, डागा महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. संगीता घई के साथ अन्य प्राध्यापकगण के अलावा कॉलेज की छात्राएं उपस्थित थी। कार्यकम की शुरूआत मां सरस्वती की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।

## होम्योपैथी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रोगों को ठीक करने में सक्षम

**रायपुर।** सैकड़ो किताबें पढ़ने से जो ज्ञान नहीं मिल पाता वो विशेषज्ञों के वक्तव्य से मिल जाता है। जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी चिकित्सा के क्षेत्र को समर्पित कर दिया, रोगों को समझने में अपना बहुमूल्य समय दिया और रोगियों के उपचार में जिनका जीवन व्यतीत हुआ, सेमिनार के जरिए उनका अनुभव सुनने को मिलता है। लोगों के बीच भ्रांति है कि होम्योपैथी जल्दी असर नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रोगों को ठीक करने में सक्षम है। होम्योपैथी में बिना साइड इफेक्ट के सस्ते में अच्छा इलाज उपलब्ध है। बस हमें इसे प्रचारित करने की आवश्यकता है। उक्त बाते मेडिकल स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने राजधानी रायपुर के सिंधु पैलेस में होम्योपैथी रिसर्च एवं डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित नेशनल होम्योपैथी सेमिनार में कही। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित थे।उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती और भगवान राम का ननिहाल है। यहां की संस्कृति और परंपरा की अलग पहचान है और सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति का उल्लेख मिलता है। श्री साव ने कहा कि देश के अच्छे रिसर्च एवं मेडिकल संस्थान का अध्ययन करके हम छत्तीसगढ़ में भी होम्योपैथी का एक अच्छा मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर तीसगढ़ में स्थापित करने का मजबूत प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सेमिनार को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास और विस्तार हमारा उद्देश्य है। होम्योपैथी, नैचुरोपैथी, एलोपैथी सभी के बीच होम्योपैथी का अपना महत्व है। हमें होम्योपैथी का तात्कालिक और लम्बे समय तक लाभ मिल सकता है। इस अवसर पर श्री पवन साय, डॉ सुनील कुमार दास, डॉ विजय शंकर मिश्रा, डॉ संजय शुक्ला, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रदीप के. पात्रा, डॉ. जेपी शर्मा, डॉ. सुशील हरीरमानी, डॉ. धीरेंद्र तिवारी सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

# अ.भा.विद्युत टेबल टेनिस में छत्तीसगढ़ उपविजेता

## टीम इवेंट में रजत, सिंगल्स एवं डबल्स में कांस्य

**रायपुर।** 46वीं अखिल भारतीय विद्युत पुरूष टेबल टेनिस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी को उपविजेता बनने का गौरव मिला है । छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी 1रजत और 2 कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। 19-21 दिसंबर 2024 को लखनऊ में आयोजित इस टूर्नामेंट मे 9 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक जिनको, कर्नाटक ट्रांसको , पश्चिम बंगाल, असम,तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की स्टेट पॉवर यूटिलिटीज की टीमों से मुकाबला कर छत्तीसगढ़ की टीम ने टीम इवेंट में रजत, सिंगल्स एवं डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव [आई.ए.एस.]ने टीम को बधाई दी।

स्पर्धा में छत्तीसगढ़ टीम के पांच खिलाड़ी ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।टीम इवेंट के फाइनल मैच में श्री रजनीश ओबेरॉय, समीर तिवारी, टी. पी सिंह, प्रशांत बापट व अनुराग शर्मा ने मुकाबला किया । टीम के मैनेजर श्री सागर पिंपलापुरे एवं कोच श्री संजीव केशकर ने बताया कि पिछले साल छत्तीसगढ के खिलाड़ियों ने टीम इवेंट व सिंगल्स में ही जीत हासिल की थी परंतु इस वर्ष डबल्स में भी टीम ने खिताब जीता है। यह हमारे लिए विशेष उपलब्धि है।

समापन समारोह मे उत्तर प्रदेश स्टेट पॉवर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री पंकज कुमार [आई.ए.एस.] के मुख्य आतिथ्य में विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।

**छत्तीसगढ़/राजधानी**

**प्रमुख समाचार**

## आरक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करवाया जाये

**रायपुर।** कांग्रेस ने मांग किया है कि राजनांदगांव आरक्षक भर्ती घोटाला मामले की सीबीआई जांच कराया जाये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के राज में नौकरियां बेची जा रही है, युवा ठगा महसूस कर रहे है। राजनांदगांव आरक्षक भर्ती घोटाले के तार सत्ता के उच्च पदस्थ लोगों तक जुड़े हो सकते है। इस मामले में आरक्षक अनिल रत्नाकर की संदिग्ध मौत तथा उसके हथेली पर लिखे गये नोट्स बताते है कि यह मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अनिल रत्नाकर की मौत की भी जांच होनी चाहियें। सत्ता में बैठे हुये लोगों के संरक्षण के बिना इतना बड़ा भर्ती घोटाला होना संभव नहीं है। सरकार तथा पुलिस के उच्चाधिकारी, निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्यवाही की खानापूर्ति कर मामले को दबाने में लगे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आठवीं बटालियन पेंड्री में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मैनुअल और रिजल्ट में गोलमाल किया गया है। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गोला फेंक और ऊंची कूद को लेकर मैनुअल रजिस्टर में और रिजल्ट जारी करने में धांधली की गई है।

## सरकार के संरक्षण में प्रदेश में धर्मांतरण की घटनायें बढ़ गयी

**रायपुर।** धर्मांतरण के दबाव के कारण एक युवक के द्वारा की गयी आत्महत्या को कांग्रेस ने दुखद बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धर्मांतरण के दबाव में युवक की आत्महत्या भाजपा के कुशासन का आईना है। राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है प्रदेश के शहरी एवं मैदानी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण की घटनायें बढ़ गयी है। भाजपा खुद धर्मांतरण को बढ़ावा देती है फिर वर्ग संघर्ष करवाती है विपक्ष में रहते हुये धर्मांतरण के नाम पर फसाद करने वाले भाजपाई पिछले एक साल से प्रदेश में होने वाली धर्मांतरण की घटनाओं पर चुप्पी साध लिये है। यही नहीं खबरें तो यह भी आ रही है कि धर्मांतरण कराने वालों को सत्तारूढ़ दल का संरक्षण मिला हुआ है। जशपुर, बस्तर में धर्मांतरण की घटनाओं के बाद भाजपा की खामोशी इस बात का प्रमाण है कि इन घटनाओं को उसका समर्थन है।जबरन धर्मांतरण को सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिये बड़ी समस्या बताया था। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद केन्द्र में बैठी मोदी सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है।

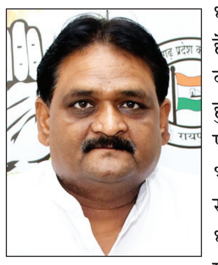

## पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा झूठा

**रायपुर ।** प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार की बदनीयती के चलते बस्तर सरगुजा संभाग में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग चुनाव लड़ने तरस जाएंगे, मैदानी क्षेत्रों में भी साय सरकार ने ओबीसी वर्ग के अधिकारों के खिलाफ़ षडयंत्र रचा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में आरक्षण को लेकर साय सरकार द्वारा जो संशोधन किया गया है वह छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी जो अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, उनके साथ अन्याय है, अत्याचार है। भाजपा से जुड़े लोग स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हक़ीक़त यह है कि आरक्षित सीटों की कुल संख्या ही अधितकम 50 प्रतिशत है, इसमें एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और ओबीसी सभी के आरक्षण शामिल हैं। सरकार ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत की है, जहां एससी-एसटी की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है, वहां पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से बस्तर, सरगुजा संभाग में ओबीसी के लिए कुछ बचा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी मूलत: आरक्षण विरोधी है।

## पत्रकारों को धमकाना संवैधानिक है क्या?

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव ने कहा है कि प्रदेश के विधानसभा परिसर में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायकों द्वारा पत्रकार के साथ की गई धक्का-मुक्की और बदसलूकी लोकतंत्र के मंदिर में कांग्रेस की गुण्डागर्दी का शर्मनाक प्रदर्शन है। श्री देव ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर देशभर में ढोल पीटते कांग्रेसी संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी का सरेआम मखौल उड़ाकर लोकतंत्र का गला घोंट रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि शुक्रवार को विधानसभा में पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करके न केवल अपने कलंकित राजनीतिक चरित्र का परिचय दिया है, अपितु उसने यह धारणा भी पुष्ट कर दी है कि कांग्रेस अब पूरी तरह हिंसक चेहरा अपना दिखा रही है। एक तरफ गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रहते बुजुर्ग सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करके उनका सिर फोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने कांग्रेस के नेताओं को खुला आह्वान किया है कि जैसे बलौदाबाजार में किया था, ठीक वैसे ही कलेक्ट्रेट के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करें।

## पत्रकार के साथ बतमीजी, धक्का मुक्की मामले में भाजपा ने पूछा

**रायपुर।** विधानसभा में कांग्रेस विधायकों द्वारा पत्रकार सुनील नामदेव के साथ की गई धक्कामुक्की और धमकीबाजी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कांग्रेस से पूछा है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि कांग्रेस को विधानसभा में झूठ बोलना पड़ा? पूर्व मुख्यमंत्री जिस विधानसभा का मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल नेतृत्व करते रहे उन्हें आखिर वहां महाझूठ क्यों बोलना पड़ा? जिस पत्रकार के साथ कांग्रेस के लोगो ने धक्कामुक्की की, उसे धमकाया, उसे भूपेश बघेल ने फर्जी पत्रकार बताया और कहा कि वह पत्रकार के भेस में घुस आया था यह सिक्योरिटी लेप्स का मामला है जबकि पत्रकार सुनील नामदेव के पास न सिर्फ 16 से 20 दिसंबर 2024 तक हुए विधासनभा सत्र का प्रवेश पास था बल्कि वह छत्तीसगढ़ विधानसभा पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के सदस्य भी है जिसमें प्रदेश के कुछ चुनिंदा पत्रकार ही सदस्य है। पूर्व मुख्यमंत्री का यह कृत्य विधानसभा के प्रति लोगों के विश्वास पर आघात करने वाला कृत्य है विधानसभा में कहे गए शब्दों को जनता पूर्णत- सत्य मानती है विधानसभा के प्रति जनता श्रद्धा भाव रखती है ऐसे में एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में इस प्रकार से झूठ कहना ,जनता को गुमराह करना, न सिर्फ निंदनीय है बल्कि और गैरसंवैधानिक भी है। जिस संविधान को हाथ में लेकर कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं।

# सीखने के लिए सदैव सतत् इच्छा होनी चाहिए : श्री डेका

रायपुर। **जीवन में आगे बढ़ने के लिए** सीखना जरूरी है और सीखने के लिए सदैव एक सतत् इच्छा होनी चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है और सीखने की कोई उम्र नही होती। अच्छे इंसान बनें क्योंकि अच्छे व्यक्ति ही बेहतर समाज का निर्माण करते है। यह उद्गार राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज आईसीएफएआई विश्वविद्यालय रायपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया।

दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले 21 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 18 विद्यार्थियों को रजत पदक सहित 362 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की अधिक संख्या है। यह देख कर उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि महिला सशक्तिकरण दिन ब दिन बहुत बेहतर हो रहा है।उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करें तो आप की सफलता निश्चित है। उज्जवल भविष्य के लिए इच्छा शक्ति और अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़े। समाज आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है उसके लिए काम करें। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की मेहनत और योग्यता से भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। निजी उच्च शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइन का पूर्णत: पालन करें और शिक्षा का स्तर बढाएं। शिक्षा एक नोबल व्यवसाय है। केवल विशाल भवन बनाकर शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना जरूरी है। शिक्षा केन्द्र को एक व्यवसाय का संस्थान न बनाया जाए।राज्यपाल ने पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि हमेशा श्रेष्ठता की ओर बढ़ते रहें।समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर आर. पी. कौशिक ने भी अपना संबोधन दिया। कुलपति डॉ. एस. पी. दुबे ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमेन श्री बृजेश चंद्र मिश्रा, विश्वविद्यालय के कुलसचिव, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, छात्र-छात्राएं एवं उनके पालकगण उपस्थित थे।

# आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने ली रेडियोडायग्नोसिस विभाग की समीक्षा बैठक

## पीजी थर्ड ईयर के छात्रों से लिया कक्षाओं के संबंध में फीडबैक

**रायपुर।** आयुक्त चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) श्रीमती किरण कौशल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के बोर्ड रूम में रेडियोडायग्नोसिस विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभाग के पीजी थर्ड ईयर के छात्रों से शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में फीडबैक लिया। बैठक में उनके साथ चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी तथा अम्बेडकर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर भी मौजूद रहे। अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने बताया कि बैठक का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा और मरीजों के लिए उपलब्ध उपचार व्यवस्था को और भी अधिक सुदृढ़ बनाना है। यही कारण है कि आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा लगातार विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है और प्रोफेसर तथा छात्रों से विभाग के संदर्भ में फीडबैक लिया जा रहा है। इसी तारतम्य में सर्जरी और पीडियाट्रिक विभाग की समीक्षा बैठक पूर्व में आयोजित की जा चुकी है जिसमें उनकी अकादमिक गतिविधियों के बारे में विभाग के डॉक्टरों तथा छात्रों के माध्यम से जानकारी ली गई। स्वास्थ्य सुविधाओं को और दुरुस्त बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी लिए। विभिन्न विभागों ने आवश्यक उपकरणों की जरूरत बताई है। इसके संबंध में कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा द्वारा सूची बनाकर ऑटोनॉमस तथा सीजीएमएससी के माध्यम से उनके सुधार एवं क्रय के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाये जाने की बात कही गई है।


आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर ( छ.ग. ) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर ( छ.ग. ) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.